कमल संदेश
ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक

संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य

सत्यपाल

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल
विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798
Qku (dk-) : +91(11) 23381428
QDI : +91(11) 23387887
पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

ई–मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय–सूची

कटरा से उधमपुर के लिए पहली रेल सेवा का शुभारम्भ..... 7
श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी–सी23 की सफल उड़ान..... 9

लेख

आपातकाल की पीड़ादायक स्मृतियां
– **अरुण जेटली**..... 11
माओवाद के खिलाफ शंखनाद
– **बलबीर पुंज**..... 13
कमजोर कांग्रेस की कहानी
– **ए. सूर्य प्रकाश**..... 20
एक माह के कार्यकाल में अच्छे दिनों की बिसात
– **जयकृष्ण गौड़**..... 22

साक्षात्कार

श्री जुआल ओराम, केन्द्रीय जनजाति कार्य मंत्री..... 15

अन्य

नवनिर्वाचित सांसदों का दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर..... 24
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती कार्यक्रम..... 26
भाजपा मानवाधिकार प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय कार्यसमिति बैठक..... 27

प्रादेशिक समाचार

मध्यप्रदेश..... 28
छत्तीसगढ़..... 29
राजस्थान, गुजरात..... 30

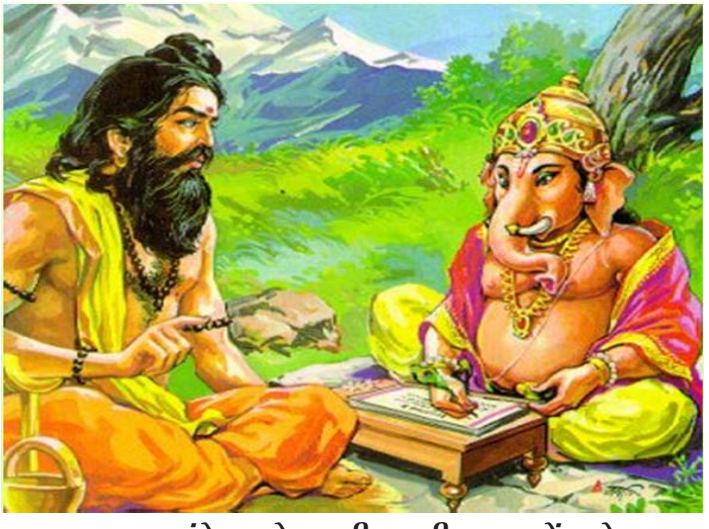

कमल संदेश के सभी सुधी पाठकों को
गुरु पूर्णिमा (12 जुलाई) की हार्दिक शुभकामनाएं

बापू की सीख

गांधी जी के करीबी मित्रों में से एक थे डॉ. प्राणजीवन मेहता। रेवाशंकर और जगजीवन दास डॉ. मेहता के भाई थे। गांधी जी के प्रति रेवाशंकर के मन में अपार श्रद्धा थी। इसलिए, गांधी जी जब मुंबई जाते तो प्राय: रेवाशंकर के घर पर ही ठहरते थे। रेवाशंकर बापू का खूब स्वागत-सत्कार करते थे। एक दिन गांधी जी मुंबई आए तो उनके साथ आनंदस्वामी भी थे। रेवाशंकर उन्हें देख बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों का यथोचित स्वागत किया। आनंदस्वामी की रेवाशंकर के रसोइए के साथ किसी बात पर अनबन हो गई। रसोइए ने तैश में आकर कुछ ऐसा बोल दिया, जो आनंदस्वामी को बहुत बुरा लगा। वह क्रोधित हो उठे और उन्होंने रसोइए को चांटा जड़ दिया।

शिकायत गांधी जी तक जा पहुंची। उन्होंने आनंदस्वामी को बुलाकर समझाया, तुम्हारा यह आचरण अशोभनीय है। तुमने ऐसा क्यों किया? आनंदस्वामी ने जवाब दिया, मुझे क्रोध आ गया था। इस पर गांधीजी बोले, 'क्रोध में भी प्राय: अपने से कमजोर लोगों को ही निशाना बनाते हैं। यदि बड़े लोगों से तुम्हारा ऐसा झगड़ा हो जाता तो उन्हें तो तुम थप्पड़ नहीं लगाते। वह नौकर है, इसलिए तुमने उसे चांटा जड़ दिया। अभी जाकर क्षमा मांगो।'

जब आनंदस्वामी ने आनाकानी की तो गांधी जी ने कहा, अपने अपराध का प्रायश्चित तभी होता है, जबकि पीड़ित से सच्चे हृदय से क्षमा मांग ली जाए। क्षमा से न केवल अपराध का बोझ समाप्त होता है, बल्कि आत्म परिष्कार भी होता है। तुम स्वयं में सुधार नहीं कर सकते तो मेरे साथ भी नहीं रह सकते। आनंदस्वामी ने तत्काल रसोइए के पास जाकर उससे क्षमा मांग ली।

संकलन : लखविन्दर सिंह

(नवभारत टाइम्स से साभार)

उन्होंने कहा था...

भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता-जागता राष्ट्रपुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, गौरी शंकर शिखा है। कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं। विन्ध्याचल कटि है, नर्मदा करधनी है। पूर्वी और पश्चिमी घाट, दो विशाल जंघाएँ हैं। कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर इसके पग पखारता है। पावस के काले-काले मेघ इसके कुंतल केश हैं। चाँद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं। यह वन्दन की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, अभिन्नदन की भूमि है। यह तर्पण की भूमि है। इसका कंकर-कंकर शंकर है, इसका बिंदु-बिंदु गंगाजल है। हम जिएँगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए।।

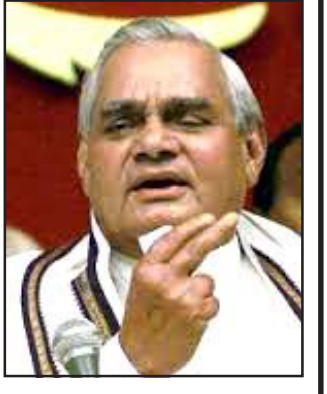

- अटल बिहारी वाजपेयी

समाज और देश के बीच सरकार सेतु का काम करे

समाज के हर वर्ग को और समाज के विशेष वर्गों को जोड़ने का सुनहरा अवसर भाजपा को और भाजपा की केन्द्र सरकार को मिला है। समाज में परिवर्तन लाने के लिए समाज को खड़ा करना पड़ता है। सरकार वही अच्छी कहलाती है जो समाज को भी अपने साथ खड़ा कर ले। वर्तमान एनडीए सरकार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह प्रयास है कि समाज उनके पीछे खड़ा हो। परिवर्तन की अगुआई समाज करे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी मानना है कि सरकार परिवर्तन ही हमारा उद्देश्य नहीं बल्कि समाज में परिवर्तन हमारा मुख्य उद्देश्य है।

वर्तमान सरकार से देश को बहुत आशाएं हैं। नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत की दृष्टि भी जनता के सामने रखी है। पिछले दस वर्षों से जनता तत्कालीन यूपीए सरकार से कट चुकी थी। सरकार नाम की चीज नहीं बची थी। लेकिन अब माहौल बदला सा है। मोदी सरकार को जनता अपनी सरकार मानती है। मानती ही नहीं, अपना अधिकार जमाती है। यही कारण है कि मोदी सरकार का दायित्व पिछली अन्य सरकारों से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। समाज में जो अच्छे लोग हैं, उनको तलाशने की और तराशने की आवश्यकता है। भारत बहुत बड़ा देश है। अनेक विविधताओं से जुड़ा हुआ है। हमारे लोकतंत्र का सौंदर्य ही विविधता में एकता है। पिछले कुछ वर्षों में जो सरकार थी, उसने सब कुछ सरकार के भरोसे करना चाहा, जो कि संभव नहीं था। सरकार वह अच्छी होती है जो समाज का विश्वास जीतती है और समाज को साथ लेकर चलती है। समाज को भी समझना होगा कि सरकार लाना ही उनका दायित्व नहीं है, सरकार चलाना भी उनका दायित्व है। 'कोऊ नृप होय हमें का हानि', यह कहने से काम नहीं चलेगा। सरकार वही अच्छी होती है जो समाज के प्रति जिम्मेदार होती है और समाज वही अच्छा होता है जो सरकार पर सतत निगरानी रखता है।

भारतीय जनता पार्टी को अथक प्रयत्न करना होगा। सरकार लाने मात्र से काम नहीं होता। सरकार समाज से जुड़े, यह प्रयत्न भाजपा को करना होगा। समाज के उन लोगों को जो अपने-अपने क्षेत्र में तज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं, अतिरिक्त जानकार हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं, ऐसे लोगों के बीच जाकर उन्हें सरकार से जोड़ना, देश को विकास की ओर ले जाने में सराहनीय कदम माना जाएगा। समाज में अनेक ऐसे लोग हैं, जो कारगर हैं पर उन्हें अवसर नहीं मिला है, उन्हें सहारा नहीं मिला है, ऐसे लोगों तक सरकार को पहुंचाना होगा।

गांव-गांव में नित नए आविष्कार होते हैं। ग्रामवासी अपनी जरूरतों के लिए गांव के भरोसे ही काम करते हैं। भारत में आज अनेक ऐसे गांव हैं जो स्वावलंबी हैं। समाज ने मिलकर गांव को अपने पैरों पर खड़ा किया है। ऐसे गांव की तलाश सरकार और भाजपा दोनों को करनी होगी। यदि गांव स्वावलंबी होंगे तो समाज स्वावलंबी होगा।

समाज के उन समाजसेवियों तक जो ग्राम-स्वराज की कल्पना को धरती पर साकार कर रहे हैं, बिजली से लेकर पानी तक में गांव को स्वावलंबी बनाया है, गांव में चहुंमुखी विकास के द्वार खोले हैं, पशु संवर्धन हो या हाट-बाजार की प्रगति हो, इतना ही नहीं तो कुटीर उद्योगों का जाल बिछाया हो, ऐसे गांव के दर्शन करने होंगे। गांव हमारी प्रशासनिक इकाई है। उसे स्वावलंबी समाज

ही संवार सकता है। इसलिए समाज में व्याप्त उन समाजसेवियों की और जो समाज में शिल्पी बनकर काम करते हैं, उन पर ध्यान देना होगा।

देश को सबकी आवश्यकता है और सबको देश की आवश्यकता है। सरकार समाज और देश के बीच सेतु बनने का काम कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के विचारक पं. दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय का सपना साकार करने के लिए आज आवश्यकता यह है कि गांव जगे और गांव का समाज जगे। खेल, विज्ञान, कला, कुटीर उद्योग, ग्रामीण विकास, सिंचाई, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, जैसे अनेक क्षेत्रों में कर्मजीवियों ने अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उन उदाहरणों तक और उदाहरण प्रस्तुत करने वालों तक सरकार की किरणें पहुंचनी चाहिए। प्रतिभाएं गांव-गांव में हैं। आवश्यकता यह है कि उन प्रतिभाओं को सरकार के माध्यम से अवसर मिले। स्वतंत्रता के बाद अधिकांशत: अब तक जो भी सरकारें आईं वह सरकार चलाती रही पर आंखों से समाज ओझल करती रहीं। समाज बिना सरकार नहीं। उपरोक्त कार्य कठिन है, पर असंभव नहीं। सरकारी मशीनरी अब तक ग्रामीण प्रतिभाओं और उच्च कोटि के समाजसेवियों को हतोत्साहित करती रही है। लेकिन मोदी सरकार से नई उम्मीदें जगी हैं। अत: भाजपा सांसदों, विधायकों, समर्थकों सहित भाजपा कार्यकर्ताओं की यह महती जिम्मेदारी हो जाती है कि वे समाज के सबलतम अगुआई करने वाले लोगों के हाथ सरकार के हाथ तक ले जाएं। समाज और सरकार का हाथ जब मिलेगा तो लोकतंत्र की मजबूती बढ़ेगी। लोकतंत्र की मजबूती बढ़ेगी तो देश बढ़ेगा। देश बढ़ेगा तो हमारा वैभवशाली देश का सपना साकार होगा।■

जम्मू-कश्मीर कार्यकारिणी बैठक संपन्न

भाजपा ने अगले विधानसभा चुनावों में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कश्मीर सहित मुस्लिम-बहुसंख्यक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया है।

पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में जम्मू में 24 जून को राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) श्री रामलाल उपस्थिति रहे। इस बैठक में तय किया गया कि मुस्लिम बहुत क्षेत्रों पर ध्यान देते हुए मुस्लिमों के साथ सम्पर्क बढ़ाया जाए तथा दूर-दराज के इलाकों में उनके वोटों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया जाए। यह भी तय किया गया कि मुस्लिम बहुल कश्मीर में मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए चुनाव घोषणा-पत्र में मुस्लिम-अनुकूल नीतियां तैयार की जा सकती हैं।

बैठक में यह भी निर्णय लिया कि आप्रवासियों, शरणार्थियों, किसानों, सीमावर्ती निवासियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य आर्थिक रूप से या सामाजिक पिछड़े समूहों के साथ चुनावी अभियान में सम्पर्क किया जाए। पार्टी को एसपीओ और वीडीसी का मुद्दा भी उठाया जाना चाहिए।

पार्टी ने कश्मीर क्षेत्र के लिए चुनाव अभियान समिति बनाने का भी लिया जिसके प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव जगत प्रकाश नड्डा होंगे और लद्दाख में जम्मू-कश्मीर सह-प्रभारी आर.पी. सिंह को मत रणनीति समिति का नेतृत्व प्रदान किया गया।

बैठक में राज्यमंत्री, पीएमओ, डा. जीतेन्द्र सिंह, प्रदेशाध्यक्ष और सांसद जुगल किशोर शर्मा, जम्मू-कश्मीर सह-प्रभारी आरपी सिंह, पार्टी विधानमण्डल के नेता अशोक खजुरिया, राष्ट्रीय सदस्य डा. निर्मल सिंह और शमशेर सिंह मन्हास, प्रदेश महासचिव अशोक कौल, कविन्द्र गुप्ता, बाली भगत, राजीव जसरोटिया और वरिष्ठ नेता फारूक खान उपस्थित रहे।

हरियाणा भाजपा राज्य कार्यकारिणी बैठक आयोजित

हरियाणा भारतीय जनता पार्टी ने जून में एक उच्च-प्राप्त शक्ति समिति को अम्बाला छावनी के विधायक अनिल विज के नेतृत्व में राज्य में कांग्रेसी शासन के खिलाफ आरोपपत्र तैयार करने का दायित्व दिया गया है। कुरूक्षेत्र में 24 जून को आयोजित बैठक में राज्य कार्यकारिणी ने यह निर्णय लिया। श्री विज से कहा गया कि वे भूपेन्द्र सिंह हुड्डा सरकार के गलत कार्यों के आंकड़े तैयार करें। राज्य कार्यकारिणी ने इस बात पर भी चर्चा हुई कि क्या हरियाणा जनहित कांग्रेस (एचजेसी) के साथ गठबंधन किया जाए या नहीं, परन्तु इस विषय को पार्टी के केन्द्रीय संसदीय बोर्ड पर निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया गया।■

कटरा से उधमपुर के लिए पहली रेल सेवा का शुभारम्भ

हम जम्मू-कश्मीर के विकास को ऊर्जावान और गतिवान बनाएंगे : नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द मोदी ने 4 जुलाई को श्री माता वैष्णोदेवी कटरा-उधमपुर रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री कटरा रेलवे स्टेशन से उधमपुर के लिए पहली रेल सेवा को हरी झंडी दिखाई और रेल में यात्रा करने वाले विद्यालय के छात्र-छात्राओं से बातचीत की। इस रेल को बच्चों के ''भारत माता की जय'' उद्घोष के साथ रवाना किया गया।

प्रधानमंत्री ने रेलवे स्टेशन का भी दौरा किया और सुझाव दिया कि स्टेशन की ऊर्जा आवश्यकताओं को सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि कटरा रेलवे स्टेशन को पर्यावरण अनुकूल और लोगों के अनुकूल रेलवे स्टेशन बनाया जाना चाहिए। जिससे सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा।

इस मौके पर, कटरा में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान में जारी अमरनाथ यात्रा और रमजान का पवित्र महीना तथा अब श्री माता वैष्णोदेवी के भक्तों को उनके करीब लाने वाली इस नई रेल लाइन के समागम से एक बेहद पवित्र अवसर बन गया है। श्री मोदी ने कहा कि यह रेलवे लाइन सिर्फ जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए ही नही, बल्कि पवित्र वैष्णोदेवी की गुफा की यात्रा के इच्छुक 125 करोड़ भारतीयों और सम्पूर्ण देश के लिए एक उपहार है और उन्हें इस उपहार को देते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने रेल मंत्री को सुझाव दिया है कि इस रेल का नाम श्री शक्ति एक्सप्रेस होना चाहिए। उन्होंने श्रद्धालुओं के लाभ के लिए रेलवे स्टेशन पर उपयोग की जाने वाली सुविधाओं और बेहतर तकनीकों के लिए माता वैष्णोदेवी गुफा बोर्ड को भी शुभकामनाएं दी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू और कश्मीर का विकास बिना बाधा के जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कटरा में नए रेलवे स्टेशन के साथ राज्य में और अधिक शानदार विकास किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जम्मू-कश्मीर से पूर्वोत्तर तक के हिमालयी राज्यों के लिए समान विकास मॉडल की दिशा में काम करेगी।

यह रेलवे लाइन सिर्फ जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए ही नही, बल्कि पवित्र वैष्णोदेवी की गुफा की यात्रा के इच्छुक 125 करोड़ भारतीयों और सम्पूर्ण देश के लिए एक उपहार है और उन्हें इस उपहार को देते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कटरा अब जम्मू और कश्मीर के विकास में केन्द्र बिन्दु बन चुका है और यह राज्य के विकास की गति का इंजन बनेगा। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार बनिहाल तक रेल सेवा के विस्तार के माध्यम से

श्री वाजपेयी के स्वप्न को पूर्ण करने की दिशा में कार्य करेगी।

श्री मोदी ने इस तथ्य का भी उल्लेख किया कि रेल और बस संपर्क को पहली बार जोड़ा जा चुका है। इस सुविधा के माध्यम से यात्री एक ही टिकट के माध्यम से रेल अथवा बस दोनों से यात्रा कर सकेगा। उन्होंने इस सुविधा को एक मिश्रित मॉडल का नाम दिया। उन्होंने कहा कि कटरा को देशभर से 6 युगल रेलों के माध्यम से भी जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भारत के लोगों को विश्वास दिलाया कि बड़े शहरों और जम्मू जैसे महत्वपूर्ण स्थलों का आधुनिकीकरण उनकी सरकार की प्राथमिकता है।

इस दिवस के महत्व पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि इस रेल के माध्यम से जम्मू-कश्मीर के विकास को गति और उड़ी-2 पनबिजली परियोजना के माध्यम से ऊर्जा मिली है, जिसका वह दिन में उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि वह माता वैष्णोदेवी के आशीर्वाद से देश की विकास यात्रा की शुरूआत कर रहें हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार इस विकास यात्रा को आगे ले जाएगी, नए आयाम स्थापित करेगी और आम आदमी के लाभ की दिशा में कार्य करेगी। श्री मोदी ने कहा कि उनका उद्देश्य विकास और समग्र लाभ के माध्यम से जम्मू और कश्मीर के लोगों का दिल जीतना है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी मंशा किसी राजनीतिक जीत या हार की नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर ने, कठिन समय गुजारा है, सत्ता में हों या न हों उनकी यह इच्छा और दायित्व है कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके, उनकी आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके, युवाओं को रोजगार और हर स्तर के व्यक्ति तक पहुंच बनाई जा सके।

इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य में रेल लाने का श्रेय सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दिया जाना चाहिए। उन्होंने राज्य में रेल नेटवर्क के आगे विस्तार तथा जम्मू रेलवे स्टेशन का उन्नयन किए जाने की भी अपील की।

रेल मंत्री श्री सदानंद गौडा ने कहा कि माता वैष्णोदेवी के भक्तों की इच्छा को एक लंबे समय के बाद पूर्ण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमत्री श्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि माता वैष्णोदेवी के भक्तों की इच्छा को प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री नरेन्द्र मोदी के राज्य में पहले दौरे के माध्यम से पूर्ण किया गया है।

इस अवसर पर जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल श्री एन.एन. बोहरा, राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, रेल मंत्री श्री सदानंद गौडा, रेल राज्यमंत्री श्री मनोज सिन्हा और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री श्री जितेन्द्र सिंह उपस्थित थे।■

प्रधानमंत्री ने डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिवस के अवसर पर 6 जुलाई को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया :

''हमारी प्रेरणा के स्रोत डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके जन्मदिवस पर श्रद्धांजलि। देश को उन्होंने अमूल्य योगदान दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए जनता की सेवा ही सबसे ज्यादा महत्व रखती थी। वह हमेशा युवाओं को शिक्षित करने के बारे में बात किया करते थे। आइए, हम डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर चलने के लिए खुद को समर्पित करें।''■

प्रधानमंत्री ने श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी–सी23 की सफल उड़ान देखी

''भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम मानवता की सेवा के उद्देश्य से प्रेरित है''

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्रीहरिकोटा से पोलर सेटेलाईट लाँच वेहिकल- पीएसएलवी-सी23 का सफल प्रक्षेपण देखा। मिशन कंट्रोल सेंटर से अपने बधाई संदेश में उन्होंने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को हितधारकों के साथ मिलकर शासन प्रणाली तथा विकास में अंतरिक्ष विज्ञान का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो महारथ हासिल है, वे उसे सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक विकास तथा संसाधनों के संरक्षण के लिए पूरी तरह से उपयोग करें।

भारत की 'वसुधैव कुटुम्बकं' की प्राचीन मान्यताओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम मानवता की सेवा के उद्देश्य से प्रेरित है, न कि शक्तिशाली बनने के उद्देश्य से। उन्होंने कहा कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की एक उज्ज्वल परम्परा है, जिसमें अंतरिक्ष विज्ञान भी शामिल है। श्री मोदी ने कहा कि भास्कराचार्य तथा आर्यभट्ट जैसे प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक कई पीढ़ियों को प्रेरित कर रहे है। उन्होंने कहा कि भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लाभ विकासशील देशों, विशेषकर पड़ोसी देशों के साथ सांझा करना चाहिए। उन्होंने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का आह्वान किया कि वे सार्क देशों के लिए कृत्रिम उपग्रह तैयार करें, जिसकी सेवाएं अपने पड़ोसी देशों को भारत की ओर से एक उपहार के तौर पर दिया जाए।

श्री मोदी ने कहा कि पूरी तरह से स्वदेशी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय दबाव तथा बाधाओं के बीच विकसित हुआ है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में ''हमने सामान्य की स्थिति से उपर उठकर उत्कृष्टता की स्थिति हासिल की है।'' उन्होंने कहा कि चंद्रमा मिशन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सोच से प्रेरित था। उन्होंने कहा कि मंगल मिशन तथा उपग्रह आधारित नौ-वहन इन दिनों चल रही परियोजनाओं में से एक हैं।

आम आदमी के लिए अंतरिक्ष तकनीकी के लाभ का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे आधुनिक संचार-व्यवस्था संभव है, सुदूर गांवों में बच्चों को स्तरीय शिक्षा प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है तथा टेलीमैडिसन द्वारा बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती है। डिजीटल भारत के हमारे स्वप्न को साकार करने

में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है- कम्प्यूटर से जुड़े 125 करोड़ भारतीयों की शक्ति।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर विकास हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने अत्याधुनिक उपग्रहों के विकास तथा सेटेलाईट फुटप्रिन्ट बढ़ाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि भारत के पास विश्व के लिए सर्विस प्रोवाईडर प्रक्षेपित करने की क्षमता है और इस उद्देश्य की ओर काम करना होगा।

प्रधानमंत्री ने भारत के युवा वर्ग को अंतरिक्ष कार्यक्रमों से जोड़ने का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि श्रीहरिकोटा में युवा वैज्ञानिकों को मिलकर तथा उनके काम एवं उपलब्धियों को देखकर वे बेहद खुश हुए। उन्होंने डॉ. के. राधाकृष्णन के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए उनकी सोच का पैमाना, उसकी गति तथा कौशल इत्यादि बेहतरीन है। कुछ ही महीनों में मंगल ग्रह की कक्षा में हमारे वायुयान को स्थापित करने में जुटे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी।

अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों भाषाओं के मिले-जुले भाषण में श्री मोदी ने भारतीय वैज्ञानिकों की कई पीढ़ियों की तपस्या का जिक्र किया और कहा कि उपनिषद् से उपग्रह तक की यात्रा एक लंबी यात्रा रही है।

उन्होंने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के दौरे के समय वे वैज्ञानिकों की चार पीढ़ियों से मिले हैं।

इस अवसर पर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल श्री नरसिम्हन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू, संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, अंतरिक्ष-सचिव डॉ. राधाकृष्णन, तथा प्रो. यू.आर. राव और डॉ. कस्तूरीरंगन जैसे वरिष्ठ वैज्ञानिक उपस्थित थे। ■

नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देंगे : राजनाथ सिंह

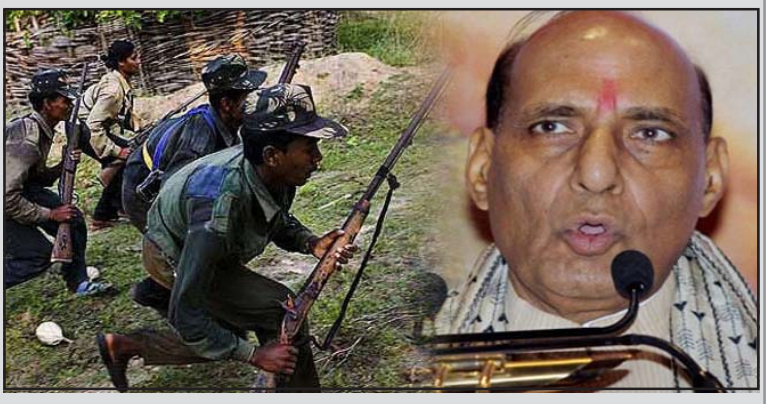

केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नक्सल समस्या से सख्ती से निपटने के संकेत देते हुए 27 जून को कहा कि नक्सलियों से बातचीत नहीं की जाएगी बल्कि सरकार समस्या के स्थायी समाधान के लिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाएगी।

श्री सिंह ने नक्सल प्रभावित दस राज्यों के अधिकारियों के साथ यहां इस समस्या पर विस्तार से विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि सरकार नक्सलियों के साथ बातचीत की पहल नहीं करेगी बल्कि समस्या के स्थायी समाधान के लिए संतुलित रुख अपनाएगी। इसमें प्रभावित क्षेत्रों में विकास की गतिविधियों को तेज किया जाएगा और जरूरत पडने पर वहां तैनात सुरक्षा बलों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। श्री सिंह नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाने की दिशा में कदम उठाते हुए कहा कि उन्हें विशेष भत्ता दिए जाने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि नक्सली हिंसा का रास्ता अख्तियार करते हैं तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अधिकारियों ने सिंह को प्रभावित राज्यों में इस समस्या से उत्पन्न स्थिति तथा इससे निपटने में आ रही कठिनाइयों से अवगत कराया। गृह मंत्री ने इन राज्यों द्वारा चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियानों और उपायों की भी समीक्षा की। उन्होंने इन राज्यों से केंद्र तथा अन्य राज्यों के साथ तालमेल के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा। नक्सलियों द्वारा दूरसंचार मंत्रालय के टावरों को निशाना बनाए जाने के बारे में भी बैठक में चर्चा हुई। अधिकारियों ने टावरों की सुरक्षा बढ़ाए जाने की ओर गृहमंत्री का ध्यान आकृष्ट किया। श्री सिंह ने आश्वासन दिया कि इन क्षेत्रों में और बेहतर संचार सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। बैठक में छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों, अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों और गृह तथा संचार मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।■

आपातकाल की पीड़ादायक स्मृतियां

✍ अरुण जेटली

मेरे जैसे बहुत से लोग, जिन्होंने दिल्ली में आपातकाल के अनुभव भोगे और सफलतापूर्वक इसके खिलाफ लड़े, यह हमारे जीवन का बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। शायद आपातकाल मेरे जीवन का सर्वोत्कृष्ट राजनैतिक शिक्षा साबित हुई। इसी ने हमें सिखाया कि कई समझौते ऐसे भी होते हैं जिन्हें किसी भी हालत में नहीं किया जाना चाहिए।

26 जून 2014 आपातकाल की 39वीं जयंती है। आपातकाल 19 महीने तक भारतीयों (चुनाव के दो महीने छोड़कर) पर दमनचक्र का वह दौर था जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में शायद सबसे निकृष्ट काल कहा जा सकता है। आज अधिकांश ऐसे भारतीय भी हैं जिन्होंने इस क्रूरता के दर्शन नहीं किए। मैं आपातकाल के दिनों को अपने व्यक्तिगत संस्मरण पेश करना चाहता हूं।

श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में रायबरेली से सोशलिस्ट नेता राजनारायण के खिलाफ चुनाव लड़ा था। राजनारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्रीमती इंदिरा गांधी की वैधता को चुनौती दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनके वकील शांति भूषण थे। भारतीय समाचार पत्रों में इस मुकदमें की चर्चा खूब रही और राष्ट्रीय जिज्ञासा भी बनी रही। 12 जून 1975 को इलाहाबाद कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने भ्रष्ट आचरण के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर दिया। प्रधानमंत्री सांसद नहीं रहीं। उन्हें आगे भी 6 साल तक चुनाव न लड़ने के लिए निर्योग्य बना दिया।

श्रीमती गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका प्रस्तुत करना बेहतर समझा। उनकी ओर से नानी पालखीवाला इस मामले में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट के जज ने उन्हें आंशिक स्थगन मंजूर किया। वह सदन में उपस्थित हो सकती थीं, परन्तु उन्हें वोट देने से वंचित किया गया। इसी बीच, श्री जय प्रकाश नारायण द्वारा कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाया गया राष्ट्रीय आंदोलन अधिक लोकप्रिय होता चला गया। दिल्ली में गैर-कांग्रेसी राजनैतिक पार्टियों की दो दिवसीय कांफ्रेंस गांधी पीस फाउण्डेशन में आयोजित हुई। 25 जून 1975 को सायंकाल रामलीला मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन हुआ जिसे जय प्रकाश नारायण तथा अन्य कई नेताओं ने सम्बोधित किया। रैली में उपस्थिति के बाद मैं देर रात घर लौटा। उस समय मैं लॉ फैक्ल्टी में दूसरे वर्ष में अध्ययन कर रहा था। तब मैं दिल्ली यूनीवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का प्रेजीडेण्ट था और जेपी की कमिटी फार यूथ एंड स्टूडेंट आर्गेनाइजेशन का संयोजक था।

लगभग रात 2 बजे मेरे निवास पर खटखटाहट हुई। पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आई थी। मेरे पिताजी व्यवसाय से वकील थे और उन्होंने अपने घर के दरवाजे पर तर्क-वितर्क किया कि आखिर उन्हें यह तो बताया जाए कि किस प्रकार का अपराध किया गया है। पुलिस ने कहा कि उन्हें केवल इतनी हिदायत है कि मुझे गिरफ्तार किया जाए और वह नहीं जानते थे कि किस अपराध के प्रावधान में गिरफ्तार किया जाना है। जब यह तर्क चल रहा था तो मैं पिछले दरवाजे से निकल गया और पडौस के एक घर में चला गया।

मैंने अपने सहयोगियों को टेलीफोन किया और ब्यौरा इकट्ठा करने की कोशिश की कि क्या कुछ हो रहा है। प्रात:काल, कोई भी अखबार, नहीं निकला। बहादुरशाह जफर मार्ग पर बिजली के कनेक्शन काट दिए गए। समाचार आने शुरू हो गए कि जय प्रकाश नारायण सहित विपक्षी दलों के सभी राजनैतिक नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी भी शामिल थे। दिल्ली यूनीवर्सिटी के नजदीक तिमारपुर ऐसी गतिविधियों का केन्द्र बन गया था। सभी गिरफ्तार लोगों को वहां लाया गया और हरियाणा तथा दिल्ली की विशिष्ट जेलों में भेजा गया। अपने साथी एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ मैं लगभग प्रात: 10 बजे दिल्ली यूनीवर्सिटी कैम्पस पहुंचा ताकि वहां विरोध प्रदर्शन किया जाए। यही वह विरोध प्रदर्शन था, जो पूरे देश में आपातकाल के खिलाफ आयोजित हुआ था। विरोध प्रदर्शन में एक पुतला जलाया गया। विरोध प्रदर्शन के समाचार के कारण दिल्ली यूनिवर्सिटी कैम्पस में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों का आगमन हुआ। मैंने अपने सहयोगियों से अनुरोध किया कि वे शांतिपूर्वक चले जाएं क्योंकि पुलिस ने मुझे घेर लिया था। मैंने गिरफ्तारी दी। मुझे भी तिमारपुर पुलिस स्टेशन ले जाया गया जहां मुझे

'मीसा' के अन्तर्गत हिरासती आदेश दिया गया। मुझे दिल्ली की तिहाड़ जेल ले जाया गया जहां और भी सभी राजनेता हिरासत में रखे गए थे। हरियाणा की अम्बाला जेल में ले जाने से पहले मुझे वहां आठ दिन तक रखा गया। लगभग तीन महीने के बाद मुझे फिर से दिली लाया गया जहां मैं 19 महीने तक जनवरी 1977 के अंत तक वहीं रहा। मुझे प्रीवेंटिव डिटेंशन के अन्तर्गत 19 महीने तक रखा गया। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे दिल्ली में अपनी शिक्षा जारी रखने के अधिकार से वंचित रखा गया।

संविधान के अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल की घोषणा की गई और उसके साथ ही साथ अनुच्छेद 359 की अधिसूचना में अनुच्छेद 14, 19, 21 और 22 के मौलिक अधिकारों को भी निलम्बित कर दिया गया था। सभी समाचार पत्रों पर प्री-सेंसरशिप लगा दी गई। सेंसरिंग अथारिटी का एक प्रतिनिधि प्रत्येक समाचारपत्र और न्यूज एजेंसी में बैठा दिया गया था। कोई भी खबर, जिसमें सरकार की आलोचना की गई हो, उसे प्रकाशित होने दिया जाता था। मौलिक अधिकार निलम्बित कर दिए गए थे। सरकार के विरोध का अधिकार छीन लिया गया था। देश में कहीं भी विरोध प्रदर्शन नहीं हो सकता था। शायद सुप्रीम कोर्ट की दशा स्वतंत्रता-उपरांत निर्णयों के बारे में सबसे खराब थी, जहां बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले में कोई सुनवाई नहीं होती थी, चाहे राजनेताओं की हिरासत अवैध ही क्यों न हो! उनके पास कोर्ट तक पहुंचने का कोई साधन नहीं रह गया था और न ही कोई राहत मिल सकती थी। सरकार ने यह स्थिति अपना ली थी कि यदि कोई हिरासती मर भी जाए तो भी वह कोर्ट नहीं जा सकता था। सरकार का हुकुम मानने वाली सुप्रीम कोर्ट भी इस बात से सहमत थी। अधिकांश सांसदों को हिरासत में लिया गया था। कोई संसदीय प्रक्रिया, जिसमें सरकार की आलोचना की गई हो, उसे समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जा सकता था।

प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की घोषणा थी कि अनुशासन का युग शुरू हो गया है। उन्होंने 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की जिनमें ऐसे विचार समाहित थे जो पश्चगामी कहे जा सकते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रमों के वफादार तानाशाह देवकांत बरूआ का कहना था कि ''इंदिरा इज इण्डिया एंड इण्डिया इज इंदिरा''। श्रीमती गांधी के छोटे पुत्र संजय को भारत की युवा हस्ती के रूप में घोषित किया गया। 20 सूत्री कार्यक्रम के प्रति वफादारी की घोषणा करते हुए फिल्म अभिनेताओं और संगीतकारों को अपने कार्यक्रमों में कांग्रेस पार्टी की प्रशस्ति करने के लिए कहा गया। विरोधकर्ताओं को दण्डित किया गया। आल इंडिया रेडियो पर किशोर कुमार के गानों को बंद कर दिया गया। दूरदर्शन पर देव आनन्द की फिल्मों का प्रसारण रोक दिया गया। देश का पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन चापलूसी का साधन बना दिया गया। झूठे मुकदमें दायर किए गए और लाखों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया।

इंदिरा गांधी के अवैध चुनाव को वैध करने के लिए पीछे के समय से जन प्रतिनिधि अधिनियम में संशोधित कर दिया गया। संविधान में संशोधन कर प्रधानमंत्री के चुनाव को कोर्ट में ले जाने की मनाही कर दी गई। आपतकाल की घोषणा को कोर्ट में ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई। कांग्रेस के कुछ विरोधियों में चन्द्रशेखर भी थे, उन्हें भी हिरासत में ले लिया। गुजरात, तमिलनाडु जैसी विपक्षी पार्टियों की सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। देश की हाईकोर्टों ने हिरासत किए गए व्यक्तियों पर कुछ राहत देने का साहस दिखाया। परन्तु एकदम कमजोर और दब्बू सुप्रीम कोर्ट ने हर मामले को उलट दिया।

आपातकाल ने भारतीय संविधान के आदेश की कमजोरी दिखाई पड़ी। प्रेस को चुप करा दिया गया। न्यायपालिका को दब्बू बना कर छोड़ा गया। अधिकांश विपक्षी पार्टियां, जिनमें वामपंथी पार्टियां शामिल हैं, उन्होंने या तो आपातकाल का समर्थन किया या मामूली सा विरोध कर छोड़ दिया। जेल में हम लोगों को स्पष्ट नहीं था कि हम कब तक हिरासत में रहेंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय विसम्मति के दबाव में आकर इंदिरा गांधी को पुन: विचार करना पड़ गया। उन्होंने गलत अन्दाजा लगाया और चुनाव कराने का निर्णय लिया। जनवरी 1977 के अंत में आपातकाल में कुछ ढील दी गई और अधिकांश राजनैतिक हिरासती व्यक्तियों को जेल से रिहा करना शुरू हुआ। चुनाव में आपातकाल के प्रति गहरा आक्रोश दिखाई पड़ा। भारत के अधिकांश हिस्सों में कांग्रेस पार्टी की हार हुई। श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके पुत्र राय बरेली और अमेठी के अपने निर्वाचन क्षेत्रों से हार गए। मेरे जैसे बहुत से लोग, जिन्होंने दिल्ली में आपातकाल के अनुभव भोगे और सफलतापूर्वक इसके खिलाफ लड़े, यह हमारे जीवन का बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। शायद आपातकाल मेरे जीवन का सर्वोत्कृष्ट राजनैतिक शिक्षा साबित हुई। इसी ने हमें सिखाया कि कई समझौते ऐसे भी होते हैं जिन्हें किसी भी हालत में नहीं किया जाना चाहिए। ■

(लेखक केन्द्रीय वित्त एवं रक्षा मंत्री हैं।)

माओवाद के खिलाफ शंखनाद

✍ बलबीर पुंज

विगत 27 जून को माओवाद हिंसा से प्रभावित दस राज्यों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के महानिदेशकों के साथ हुई बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने माओवादियों से सख्ती से निबटने की घोषणा की है। माओवादी समस्या को लेकर कांग्रेस नीत संप्रग सरकार की विरोधाभासी नीतियों की तुलना में यह नई सरकार का ठोस कदम है। पूर्वोत्तर के प्रांतों में सक्रिय उग्रवादी संगठनों का प्रश्न हो या जम्मू-कश्मीर में चल रहा अलगाववाद, संप्रग सरकार ठोस कार्रवाई करने की जगह उनसे 'वार्ता' करने को बेताब रहती थी। माओवादी समस्या को लेकर भी पूर्ववर्ती सत्ता अधिष्ठान में भ्रम की स्थिति थी। गृहमंत्री के नाते पी. चिदंबरम जब कभी माओवादियों के प्रति कड़ी कार्रवाई का संकेत देते थे तो दिग्विजय सिंह सरीखे कांग्रेसी नेता उसका विरोध करते थे। तत्कालीन गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने तो इस समस्या को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सुझाव पर माओवादी समस्या को आर्थिक-सामाजिक समस्या से अधिक नहीं समझा। इस बैठक में गृहमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि माओवादियों के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा।

सामंतवाद के विरोध और दलित-वंचित के नाम पर पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से जो हिंसक आंदोलन 1967 में प्रारंभ हुआ था, वह आज फिरौती और अपहरण का दूसरा नाम है। देश के 160 से अधिक जिले माओवादी हिंसा से लहूलुहान हैं। चीन और पाकिस्तान पोषित 4,000 सशस्त्र कॉडर और करीब 36,000 माओवादी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार के सभ्य समाज को जब-तब रक्तरंजित करते आए हैं। पिछले 20 सालों में माओवादी हिंसा में 12,138 बेकसूर मारे गए हैं, जिनमें 9,471 नागरिक और 2,712 सुरक्षा जवान हैं। माओवादियों को अपने प्रभाव क्षेत्र की तराइयों, निष्ठावान कैडर और आधुनिक अस्त्रों के कारण बढ़त हासिल है। राजनाथ सिंह ने माओवादी समस्या से निबटने का जो संकल्प दिखाया है, उसका हर देशभक्त स्वागत करेगा, किंतु माओवाद से लड़ने के लिए अर्धसैनिक बलों को आधुनिक अस्त्र-शस्त्र और वायुसेना का सहयोग जरूरी है। साथ ही इन बलों की सेवा शर्तों में सुधार लाने की भी आवश्यकता है। तैनाती वाले स्थानों पर उन्हें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पातीं। माओवादी समस्या से निबटने के लिए माओवाद से प्रभावित राज्यों के बीच समन्वय और बराबर की प्रतिबद्धता आवश्यक है।

एक अनुमान के अनुसार माओवादी साल में 1800 सौ करोड़ की उगाही करते हैं। छत्तीसगढ़ माओवाद से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। इसका बड़ा कारण यहां से मिलने वाली मोटी रकम है। अकेले छत्तीसगढ़ से माओवादी सालाना 80 से सौ करोड़ रुपये की उगाही करते हैं। उनके धन का मुख्य स्रोत माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में चलने वाले विकास कार्य, विविध सरकारी योजनाएं, ट्रांसपोर्टर और उद्योग हैं। माओवादी सड़कों, भवनों के निर्माण या अन्य कार्यों के ठेकेदारों से 'प्रोटेक्शन मनी' के तौर पर कुल लागत की एक से बीस प्रतिशत राशि वसूलते हैं। माओवाद के समर्थकों का दावा है कि यह समस्या दो कारणों से पैदा हुई है। पूंजीपति-सामंती वर्ग व सूदखोर बनियों के शोषण के कारण

सामंतवाद के विरोध और दलित-वंचित के नाम पर पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से जो हिंसक आंदोलन 1967 में प्रारंभ हुआ था, वह आज फिरौती और अपहरण का दूसरा नाम है। देश के 160 से अधिक जिले माओवादी हिंसा से लहूलुहान हैं। चीन और पाकिस्तान पोषित 4,000 सशस्त्र कॉडर और करीब 36,000 माओवादी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार के सभ्य समाज को जब-तब रक्तरंजित करते आए हैं। पिछले 20 सालों में माओवादी हिंसा में 12,138 बेकसूर मारे गए हैं, जिनमें 9,471 नागरिक और 2,712 सुरक्षा जवान हैं।

आदिवासी हथियार उठाने को मजबूर हुए हैं। दूसरा, पुलिस और प्रशासन में सामंती वर्ग का प्रभुत्व होने के कारण आदिवासियों का उस स्तर पर भी शोषण होता है।

यह तर्क माओवाद से त्रस्त छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जैसे अन्य दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में कोई अर्थ नहीं रखता है। दंतेवाड़ा में सामंती वर्ग कभी रहा ही नहीं। माओवादी हिंसा से पहले मीलों तक न तो कोई पुलिस चौकी थी और न ही प्रशासनिक अमला वहां उपस्थित था। अंग्रेजी काल में यह पूरा क्षेत्र उपेक्षित रहा। वहां अंग्रेज सरकार का आधिपत्य तो था, परंतु जनता में राज्य सत्ता का ना तो प्रभाव था और ना ही विकास की किरण पहुंची। आदिवासी अलग-थलग पड़े रहे। आजादी के बाद स्थितियां बदलनी चाहिए थीं, परंतु वामपंथ से प्रभावित सत्ता अधिष्ठान ने 'आदिवासियों की अलग पहचान' अक्षुण्ण रखने के नाम पर इस पूरे क्षेत्र को मुख्यधारा से अलग रखा। सरकारी अमला भी इस दूरदराज और आधुनिक सुख-सुविधाओं से वंचित क्षेत्र में कार्य करने से कतराता था। इसके परिणामस्वरूप वहां के अधिकांश लोगों में यह भाव ही पैदा नहीं हो सका कि वे एक विशाल भारत के घटक हैं। इस शून्य का चीन और अन्य भारत विरोधी तत्वों ने लाभ उठाया, उस क्षेत्र में घुसपैठ की और वहां के भोले-भाले आदिवासियों को अपने ही देश और अपने ही इलाके के साथियों के विरोध में खड़ा कर दिया। शुरू के अस्त्र-शस्त्र, उनके उपयोग के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएं, धन, वैचारिक अधिष्ठान इत्यादि चीन ने उपलब्ध करवाए। कालांतर में ये लोग स्वावलंबी हो गए। माओवादी रक्त से भारतीय हैं, किंतु चीनी हितों के लिए अपनी जान देते भी हैं और साथी भारतीयों के प्राण लेते भी हैं। वास्तव में सामाजिक न्याय के नाम पर लड़ी जाने वाली यह लड़ाई चीन द्वारा भारत के खिलाफ छद्म युद्ध है। इस इलाके के विकास की कोशिशें माओवादियों ने सिरे नहीं चढ़ने दीं। विकास से वंचित ग्रामीण इलाकों में व्याप्त गरीबी और बेरोजगारी माओवादियों के विस्तार का साधन बनी। माओवादियों का लक्ष्य गरीब व वंचितों का उत्थान नहीं है। यदि यह सत्य होता तो सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए किए जा रहे कार्यों को बाधित क्यों किया जाता है? सड़कों को क्यों उड़ा दिया जाता है? हकीकत यह है कि उनकी हिंसा से गरीब आदिवासी ही सर्वाधिक आहत हैं। उनकी प्रेरणा चीनी साम्यवादी नेता माओ त्से तुंग है, जिसने हिंसा के बल पर चीन की सत्ता हथिया ली थी। साम्यवादी विचारधारा हिंसा और अधिनायकवादी केंद्रीय सत्ता पर विश्वास रखती है, जहां लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए कोई स्थान नहीं है। पूर्वोत्तर के राज्य अलगाववाद की चपेट में हैं और इस अलगाववादी भावना के दोहन में चर्च के एक भाग का भारी योगदान है। माओवादी अब असम के उग्रवादी संगठन उल्फा के साथ मिलकर अपहरण और उगाही का काम कर रहे हैं। माओवादी जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के अलगाववादी आतंकी संगठनों के साथ भी घनिष्ठ संपर्क में हैं। माओवादी समस्या को सामाजिक-आर्थिक समस्या मानना वस्तुत: देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है।

विदेशी आकाओं से प्राप्त धन संसाधन और प्रशिक्षण के बल पर भारतीय सत्ता अधिष्ठान, लोकतंत्र और यहां की सनातन संस्कृति को उखाड़ फेंकना माओवादियों का वास्तविक लक्ष्य है। माओवादियों ने 2050 तक सत्ता पर कब्जा कर लेने का दावा किया है। इस तरह के आंदोलन कंबोडिया, रोमानिया, विएतनाम आदि जिन देशों में भी हुए, वहां लोगों को अंतत: कंगाली ही हाथ लगी। माओ और पॉल पॉट ने लाखों लोगों की लाशें गिराकर खुशहाली लाने का छलावा दिया था, वह कालांतर में आत्मघाती साबित हुआ। माओवादियों के साथ सहानुभूति इसी विनाश को निमंत्रण देना है।

विदेशी आकाओं से प्राप्त धन संसाधन और प्रशिक्षण के बल पर भारतीय सत्ता अधिष्ठान, लोकतंत्र और यहां की सनातन संस्कृति को उखाड़ फेंकना माओवादियों का वास्तविक लक्ष्य है। माओवादियों ने 2050 तक सत्ता पर कब्जा कर लेने का दावा किया है। इस तरह के आंदोलन कंबोडिया, रोमानिया, विएतनाम आदि जिन देशों में भी हुए, वहां लोगों को अंतत: कंगाली ही हाथ लगी। माओ और पॉल पॉट ने लाखों लोगों की लाशें गिराकर खुशहाली लाने का छलावा दिया था, वह कालांतर में आत्मघाती साबित हुआ। माओवादियों के साथ सहानुभूति इसी विनाश को निमंत्रण देना है। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं।)

विशेष साक्षात्कार

आदिवासियों का कल्याण और उनकी सांस्कृतिक परम्परा को बनाये रखना सरकार की प्राथमिक प्रतिबद्धता है : जुआल ओराम

ओडिशा में सुन्दरगढ़ जिले में एक गरीब परिवार में जन्मे श्री जुआल ओराम ने उस समय एक इतिहास रच दिया जब वे अटल बिहारी वाजपेयी-नीत-एनडीए सरकार में 1999 में पहली बार भारत के केन्द्रीय जनजाति कार्यमंत्री बने। 1990 में राजनीति में भाग लेने से पहले श्री ओराम ने छह वर्षों तक 'भेल' में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में काम किया। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया जिनमें दो कार्यकाल तक भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तीन कार्यकाल ओड़िशा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष, ओड़िशा विधानमण्डल का सदस्य और केन्द्रीय सरकार तथा भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदीय समितियों का कामकाज भी शामिल है।

श्री ओराम पहली बार 1998 में 12वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे और उन्होंने हाल ही में 2014 में आयोजित चुनावों में अपनी चौथी जीत दर्ज कराई। श्री ओराम ने सदैव ही आदिवासी उद्धार और समाज के गरीब वर्गों के कल्याण में बढ़ चढ़कर काम करते हुए हाल ही में उन्होंने दूसरी बार केन्द्रीय जनजाति कार्यमंत्री बन कर सामने आए हैं।

'कमल संदेश' के लिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री जुआल ओराम ने सम्पादकीय मंडल सदस्य ***श्री रामप्रसाद त्रिपाठी*** *के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने आदिवासियों सम्बंधित चुनौतियों पर अपने स्पष्ट विचार रखे तथा देश के आदिवासी लोगों की भावी योजनाओं को सामने रखा क्योंकि ये लोग बेहद गरीबी और पिछड़ेपन के शिकार हैं। उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में आदिवासियों के तेजी से विकास करने की अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों पर भी प्रकाश डाला ताकि इन्हें विकास की धारा में शामिल किया जा सके। साक्षात्कार के कुछ अंश नीचे प्रस्तुत हैं:*

आप वाजपेयी-नीत एनडीए सरकार में पहले जनजातीय कार्य मंत्री थे। अब फिर से मोदी जी ने आप के कंधों पर जनजातीय कल्याण मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है। इस बीच के समय में आदिवासियों के जीवन स्तर में क्या कुछ परिवर्तन हुआ है?

पिछले दशक में जनजातीय कार्यमंत्री के रूप में तीन मंत्रियों ने कार्यभार संभाला और वन अधिकार अधिनियम में थोड़े परिवर्तन को छोड़कर, जिसे वाजपेयी सरकार ने आरम्भ किया था, इन मंत्रियों ने कोई खास विकास का काम नहीं किया। मुझे अपना काम उसी स्थान से शुरू करना पड़ेगा जहां से जो काम पिछले दस वर्ष पहले हुआ था।

आदिवासियों के विकास के लिए अपनी तात्कालिक प्राथमिकताएं क्या हैं और इनका दीर्घकालीन लक्ष्य क्या है?

मेरा विशेष ध्यान अपने इस कार्यकाल में आदिवासियों के जीवन स्तर, रोजगार और शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान करने पर रहेगा। मैं इस बात का भरसक प्रयास करूंगा जिससे एक ही स्थान से विभिन्न एजेंसियों और एनजीओ के माध्यम से हर प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए काम किया जाए और मंत्रालय जमीनी स्तर पर इन योजनाओं को पूरी तरह से पूरा करे।

इस समय हमारे जनजातीय समुदाय की मुख्य आवश्यकता स्वास्थ्य सुविधाएं, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल

विस्तार, परिवहन तथा संचार सुविधाएं हैं। क्या आपके पास आदिवासियों के लिए इन मुद्दों का समाधान करने की विशिष्ट योजनाएं हैं?

एनडीए के मेरे पहले कार्यकाल में इन प्रधान क्षेत्रों में शिक्षा की उत्कृष्टता, संचार और स्वास्थ्य क्षेत्रों के विस्तार करने के लिए कई योजनाएं आरम्भ की गई थीं। मेरे विचार में इस बार देश में आदिवासियों के इन प्रधान क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा और खेल-कूद अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) की दो और योजनाओं पर विशेष ध्यान देना होगा।

हर मंच पर वन भूमि स्वामित्व का मुद्दा एक प्रधान चर्चा का विषय बना रहता है। आदिवासियों के लिए भूमि अधिकारों के मुद्दे का आप कैसे समाधान करेंगे?

संविधान में एक प्रावधान है जिसमें कोई भी आदिवासी वन-भूमि पर दस वर्षो से अधिक समय तक रहता है तो उसे भूमि का मालिकाना हक मिलने का अधिकार है। इसके लिए विभिन्न कार्यालय ब्लाक स्तर, जिलास्तर और राज्य स्तर पर काम कर रहे हैं। किन्तु, किसी न किसी बहाने अधिकारीगण आदिवासियों को पट्टे देने से इंकार करते रहते हैं। इसी कारण, आदिवासियों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। मैं इस पर विशेष ध्यान दूंगा और अधिकारियों की अड़चनों का समाधान तथा योजना में बने हुए छिद्रों को हटाने का प्रयास करूंगा जिससे सामान्य आदिवासियों को इसका लाभ मिल सके।

इन विवादों के रहते हुए भूमि अधिकार का मुद्दा औद्योगिकरण और खनन विषय पर देश के आदिवासी पॉकेटों पर गहरा प्रभाव डालता है। नियमागिरी का 'वेदांता' और खण्ढाधार में 'पोस्को' इसका ज्वलंत उदाहरण हैं। आप किस रूप में इसे मुद्दे को देखते हैं?

ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो विश्व में प्रकृति की उपहार होती हैं। यदि एक बार ये नष्ट हो जाएं तो हम उन्हें फिर से निर्माण नहीं कर सकते हैं। ओड़िशा में नियमागिरी और खण्ढ़ाधार ऐसे ही उदाहरण हैं। अत:, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि इन खजानों के नष्ट होने से विकास नहीं रूकता है। विभिन्न राज्यों के पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में विकास की बजाए तो इससे और अधिक खराब स्थिति पैदा हो जाएगी। नियमगिरी में आदिवासी इसे अपना भगवान मानते हैं और इस समय पर्वतीय क्षेत्र उद्योगों से अधिक योगदान देते हैं। इसी प्रकार, खण्ढ़ाधार में, चिरंतन बहने वाली नदियां स्थानीय लोगों की जिन्दगी में विशाल योगदान देती हैं। वर्षा-प्रभावित क्षेत्र में पर्वतों की उपस्थिति के कारण ये नदियां स्थानीय समुदायों और बायोस्फीयर को जीवन देती हैं। अत: पर्वतों को नष्ट करना प्रकृति तथा स्थानीय लोगों के लिए अपूरणीय क्षति होगी।

विगत में भी, ओडिशा में 'पोस्को' इस्पात उद्योग की स्थापना करने के लिए खण्ढ़ाधार में खनन का जोरदार विरोध किया था। परन्तु, मेरी मंशा औद्योगिकरण या विकास में किसी प्रकार की बाधा बनने की नहीं है। मेरा विभाग ऐसी अनेक स्थानों का विकल्प खनन के लिए ओड़िशा सरकार को सुझाव दे सकता है। परन्तु, दुर्भाग्य है कि राज्य सरकार नियमागिरी और खण्ढ़ाधार के पर्यावरणीय-संवेदनशील आदिवासी क्षेत्रों में 'वेदांता' और 'पोस्को' में खनन अधिकार देने पर तुली हुई है। यदि ओडिशा सरकार किसी अन्य व्यवहार्य स्थानों का विकल्प का सुझाव दे तो मैं पहला व्यक्ति हूंगा जो औद्योगिक प्रक्रिया में सहयोग दूंगा।

बिहार में ट्राइबल पाकेट्स से लेकर आंध्र प्रदेश की सीमाओं तक माओवादियों के गढ़ बन गए हैं। कभी कभी तो माओवादी निर्दोष आदिवासियों की हत्या कर देते हैं और वे ही इन क्षेत्रों के विकास में बाधा बने हुए हैं। आप इन आदिवासी क्षेत्रों में माओवादियों से खतरे से निपटने के लिए क्या कदम उठाएंगे?

आदिवासियों का एक अपूर्व चरित्र होता है। उनके क्षेत्र में कुछ भी काम करने से पहले, हमें वहां के लोगों के दिल जीतने का प्रयास करना होगा और उनकी इच्छा के अनुसार विकास कार्य करने होंगे तभी कोई भी योजना सफल हो सकती है। परन्तु, हम इस तथ्य को नहीं समझते हैं। विभिन्न सरकारों ने माओवादियों को खत्म करने तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए बेइंतहा पैसा खर्च किया। परन्तु उनके प्रयास क्यों सफल नहीं हुए? मेरे विचार में इसके पीछे जो बात है, वह यह है कि न तो हमने उनकी बात सुनी और न ही हमने उन्हें उस कार्य के कार्यान्वयन का हिस्सा बनाया तो असफल होना स्वाभाविक ही था।

पहली बार, भाजपा और श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आदिवासियों का दिल जीतने की कोशिश की है।

माननीय प्रधानमंत्री ने आदिवासियों के विकास का एक विजन प्रस्तुत किया है। उन्होंने मुझ जैसे आदिवासी को आदिवासी विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। मेरे विचार में इससे उनके साथ मेरा नाता जुड़ता है और आदिवासियों ने भी इसका स्वागत किया है। हाल ही में आयोजित आम चुनावों में भाजपा को लोकसभा में अधिकतम आदिवासी सीटें प्राप्त हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि हम माओवादी मुद्दे पर उन्हें शिक्षित कर सकेंगे और उन्हें आदिवासी प्रभावित क्षेत्रों के माओवाद को समाप्त करने का प्रयास कर पाएंगे।

सेवा के नाम पर कुछ ऐसे एनजीओ हैं जिन्हें भारी विदेशी धन प्राप्त हुआ और वे इसका इस्तेमाल ऐसे प्रयोजनों के लिए करते हैं जिनमें आदिवासियों को लालच देकर उनका सामूहिक धर्मांतरण किया जाता है। आदिवासी इसका सबसे बड़ा शिकार बन जाते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसी योजना है जिससे धर्मांतरण रूक सके और ऐसे एनजीओ पर निगरानी रखी जा सके?

देश के संविधान में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है और उसमें स्पष्ट लिखा है कि कोई भी व्यक्ति पैसे का लाभ देकर या किसी अन्य प्रकार के लालच देकर धर्मांतरण नहीं कर सकता है। परन्तु अनेक संगठन है जो इस अधिकार का अतिक्रमण करती हैं। मेरे विचार में अब आदिवासियों को शिक्षित करके इस मुद्दे पर उन्हें जागृत किया जा सकेगा और धर्मांतरित होने की बजाए वे फिर से अपने पुराने धर्म की तरफ आने लगे हैं।

आदिवासी संस्कृति, परम्पराएं और साहित्य को बरकरार रखने एवं आदिवासी-प्रधान क्षेत्रों में केन्द्रीय रूप से प्रायोजित अनुसंधान क्षेत्रों की स्थापना करने के बारे में लम्बे समय से मांग की जाती रही है। इन मुद्दों की पूर्ति के लिए क्या आपकी योजना में कुछ किया जा रहा है?

राज्य सरकारों ने देश के आदिवासी प्रधान क्षेत्रों में कई आदिवासी अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की गई है। हम इनके अपग्रेडेशन (उन्नयन) और विकास के लिए ऐसे संस्थानों को और अधिक धनराशि उपलब्ध कराएंगे।

समुचित संचार व्यवस्था और स्टोरेज के अभाव के कारण बहुत से आदिवासी उत्पाद बाजार तक पहुंच नहीं पाते हैं। क्या आपके पास ऐसी कोई योजना है जिससे स्टोरेज (भण्डारण) और संचार इंफ्रास्ट्रक्चर को आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके?

हमने इस क्षेत्र के लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाई हैं। पहली बार हम 10 वन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करने जा रहे हैं। मैं जल्दी ही एक वेबसाइट की शुरूआत करूंगा और इसको विभिन्न प्रकार के वन उत्पादों की सूचना के साथ जोड़ा जाएगा और यह सूचना वास्तविक समय आधार पर उपलब्ध दरों और उत्पादों पर खरीद एजेंसियों को उपलब्ध कराई जाएंगी जिसका लाभ अन्ततः इन उत्पादों से आदिवासियों को मिलेगा।

हाल में सम्पन्न ओडिशा में विधान सभा और आम चुनावों में भाजपा का मत प्रतिशत तो बढ़ा है, परन्तु सीटों के रूप में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। इसमें कहां कोई कमी रही। आप राज्य में भाजपा का क्या भविष्य देख रहे हैं?

इस चुनाव में मत प्रतिशत के रूप में पहले के चुनाव के मुकाबले हमारा 16 से बढ़कर 22 प्रतिशत तक पहुंचा, परन्तु हम इसे सीटों के रूप में परिवर्तित नहीं कर पाए। दूसरे, लोगों में कुछ भ्रम भी पैदा हुआ क्योंकि विधान सभा और संसद दोनों के चुनावों के मतदान एक ही समय में हुआ। मतों के मामले में पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार 130 प्रतिशत बढ़ा। पिछले चुनावों में हमें 20 लाख मत मिले जबकि इस बार हमें 46 लाख वोट मिले। परन्तु मुझे आशा है कि अगले पांच वर्षों में भाजपा संगठन जमीनी स्तर पर मजबूत होगा। इसके लिए काम पहले ही शुरू हो चुका है और हम ओडिशा में व्यवहार्य विकल्प बन सकेंगे।

कुछ वर्षों पूर्व स्वामी लक्ष्मणानन्द सरस्वती, जो आदिवासी विकास और आदिवासी पुनरूद्धार का एक मुखर चेहरा था, ओडिशा के कंधमाल जिले में हत्या हो गई थी। उनकी हत्या के छह वर्षों बाद भी हत्यारे आजादी से घूम फिर रहे हैं। क्या आपके विचार में यह राज्य सरकार का षड्यंत्र नहीं है?

मेरा मानना है कि स्वामी लक्ष्मणानन्द सरस्वती की हत्या एक षड्यंत्र था। उस समय बहुत से लोगों ने इस मुद्दे पर आवाज उठाई। स्वामी लक्ष्मणानंद ने आदिवासियों के मन-मस्तिष्क को जीत लिया था और स्थानीय लोग उन्हें

शेष पृष्ठ 19 पर

हर फैसला राष्ट्रहित को मद्देनजर रखकर लिया गया है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ब्लॉग लेख में कहा कि लोगों का भरपूर प्यार और समर्थन मिला है जिससे हमें और कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिली है। उन्होंने कहा कि हमने हर फैसला देश हित को ध्यान में रखकर लिया है।

प्रधानमंत्री ने लिखा कि 26 जून मेरे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन लोगों की इच्छाएं पूरी करने की दिशा में हमारी यात्रा का एक माह पूरा हुआ है। इस दिन का एक और भी महत्व है। 1975 में मैं उस दौर का गवाह रहा हूं जिसने मुझे एक जीवंत लोकतंत्र के महत्व का पाठ पढ़ाया। 26 जून वह दिन था जब इमरजेंसी शुरू हुई थी, जिसे एक दिन पहले ही लागू किया गया था। नीचे प्रधानमंत्री के ब्लॉग का पूरा पाठ दिया गया है:

एक महीना पूरा होने के मौके पर कुछ विचार-

प्रिय मित्रों,

आज हमारी सरकार के कार्यकाल का एक माह पूरा हुआ है। मुझे जनता का जो सहयोग और प्यार मिला है, उससे मैं अभिभूत हूँ। यह हमें और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है।

पिछली सरकारों के 67 वर्षों के कार्यकाल की तुलना में एक माह कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि पिछले माह में हमारी पूरी टीम ने लोगों की भलाई के लिए हर पल कार्य किया है। हमने जो भी निर्णय लिए वे पूरी तरह से राष्ट्रहित से अनुप्रेरित है।

एक माह पूर्व जब हमने कार्यभार ग्रहण किया तो मेरी यह सोच थी कि इस स्थान पर मैं नया हूँ और कुछ लोगों की यह धारणा थी कि केन्द्र सरकार की कार्यप्रणाली की जटिलताओं को सीखने में मुझे एक साल अथवा दो साल लगेंगे। सौभाग्यवश, एक माह के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता है। मेरा विश्वास और दृढ़संकल्प लगातार बढ़ता रहा और इसका श्रेय कुछ मैं अपने मंत्रालय के सहयोगियों के सामूहिक अनुभव और बुद्धिमत्ता को देता हूँ। मेरे 4 बार मुख्य मंत्री के रूप में कार्य करने के अनुभव का भी मुझे बहुत लाभ मिला है, लोगों के प्रेम और अधिकारियों के सहयोग के कारण मेरे आत्मविश्वास को काफी बल मिला है।

पिछले कुछ दिनों से मैं विभिन्न विभागों के मंत्रियों एवं अधिकारियों से मिलता रहा हूँ उन्होंने कई detailed presentations दिये हैं। मैं मानता हूँ कि इन presentations के द्वारा विषयों को समझने में मदद मिली है और हम विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के लिए उत्कृष्ट रोडमैप बनाने में सफल रहे हैं।

पिछले महीने कई राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने शुभकामना प्रकट की एवं अपने राज्यों से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मैं आने वाले दिनों में उनके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ।

मैं अनुभव करता हूँ कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सचमुच सुधार लाने की आवश्यकता है। दिल्ली में मेरे सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि कुछ चुनिन्दा लोगों को हमें यह बताना है कि हम इस देश में अनुकूल परिवर्तन लाने के लिए ईमानदारी और निष्ठा से काम करेंगे। ये वे व्यक्ति हैं जो सरकारी कार्य प्रणाली के भीतर भी हैं और बाहर भी। पिछले माह ऐसे कुछ उदाहरण सामने आए जिनसे हमारी सरकार का कुछ लेना-देना नहीं था, लेकिन इसके बावजूद विवादों को तूल दिया गया। मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ लेकिन मैं वास्तव में यह अनुभव करता हूँ कि हमें अपनी

व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है जिससे सही लोगों के पास सही समय पर विषय सही तरीके से पहुँच सकें। ऐसा होने से स्थितियां बदलेंगी।

हर नई सरकार में ऐसा कुछ होता है जिसे हमारे मीडिया के मित्र 'honeymoon period' कहते हैं। पिछली सरकारों का यह 'honeymoon period' 100 दिनों या इससे भी ज्यादा रहा है। संयोगवश मेरी सरकार के साथ ऐसा नहीं है। 100 दिनों की बात तो छोड़िए, सौ घन्टे से भी कम समय में आरोपों का सिलसिला शुरू हो गया था। लेकिन, जब कोई राष्ट्र सेवा के एक मात्र लक्ष्य को लेकर संकल्प के साथ कार्य करता है, तो इन बातों का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। यही कारण है कि मैं बिना विचलित हुए निरंतर कार्य में रत रह पाता हूं और संतोष भी मिलता है,

26 जून मेरे लिए एक महत्वपूर्ण तारीख है। इस दिन, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने की हमारी यात्रा का एक माह पूरा हुआ है। आज के दिन का एक और भी महत्व है। 1975 में मैंने एक ऐसा महत्वपूर्ण दौर देखा था जिसने मुझे लोकतंत्र का महत्व समझाया था। 26 जून की ही वह तारीख थी जब देश में आपातकाल शुरु हुआ। यह आपातकाल एक दिन पहले ही लागू कर दिया गया था। एक युवा के रूप में परीक्षा की उन घड़ियों की कई यादें आज भी मेरे मन में ताजी हैं।

आपातकाल निश्चित तौर पर हमारे देश के इतिहास का एक सबसे काला दौर था जो इस बात की दुखद याद दिलाता है कि किस तरह बोलने की आजादी, प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी के साथ-साथ विपक्षियों को खामोश करने का प्रयास किया गया था। यदि हम अपने लोगों को विचार एवं अभिव्यक्ति की आजादी की गारंटी नहीं दे पाएंगे, तो हमारा लोकतंत्र स्थिर नहीं रह पाएगा। आज का दिन हम सबके लिए फिर से यह शपथ लेने का दिन है कि हम इन मूल्यों की रक्षा करेंगे और साथ ही good governance के माध्यम से मजबूत संस्थाओं का निर्माण करेंगे ताकि हमें फिर से वे काले दिन देखने न पड़ें। मैं एक बार फिर भारत की जनता को नमन करता हूं उनके मजबूत समर्थन और शुभकामनाओं के लिए मैं आप सभी को भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले वर्षों में हम भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

आपका

नरेन्द्र मोदी

पृष्ठ 17 का शेष...

एक संत की तरह का आदर देते थे और कंधमाल में इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए, अत: इस मुद्दे को षड्यंत्र कहने से इंकार नहीं किया जा सकता है। यदि यह षड्यंत्र नहीं था तो इतने वर्ष बीत जाने पर भी ओडिशा सरकार अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ पाई? मैंने कई बार तुरंत जांच करने की बात कही है हालांकि यह घटना अपूरणीय क्षति है और मैं फिर से राज्य सरकार से इस संवेदनशील मुद्दे पर जांच की तुरंत मांग करने की बात कहता रहूंगा।

रथ यात्रा के दौरान, ओडिशा सरकार ने पुरी में शंकराचार्य के संस्थान के प्रति असम्मान द्वारा विकृत माहौल बना दिया है। क्या आपके विचार में यह अनावश्यक नहीं है?

नि:संदेह राज्य सरकार का यह कार्य हिन्दू भावनाओं को चोट पहुंचाता है जबकि हिन्दू शंकराचार्य संस्थान का सम्मान करते थे। राज्य सरकार का धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना एक गलत मिसाल पेश करता है। यदि राज्य सरकार निष्पक्ष भाव से कार्य करे और अनावश्यक रूप से किए अपने आचरण पर माफी मांग ले तो यह मामला अब भी सुलझ सकता है।■

कमजोर कांग्रेस की कहानी

✍ ए. सूर्य प्रकाश

हाल के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी को मिली जबर्दस्त सफलता ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर राजनीतिक परिदृश्य को कई मायनों में बदल दिया है। तमाम राज्यों में अब कांग्रेस के तिरंगे का स्थान भारतीय जनता पार्टी के केसरिया रंग ने ले लिया है। देखा जाए तो कांग्रेस की हार बहुत ही व्यापक रही है, जिस कारण वह राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर खत्म होने के दौर से गुजर रही है। इसका बहुत कुछ श्रेय भाजपा को जाता है। उदाहरण के लिए 2009 के लोकसभा चुनावों में देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 29 में कांग्रेस को सफलता मिली, जबकि 2014 में यह महज 15 राज्यों तक सिमट गई। इसी प्रकार 2009 के लोकसभा चुनावों में 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तक सीमित रही भाजपा ने इस वर्ष 23 राज्यों में जीत दर्ज की। इसके अतिरिक्त कुछ संकेतों को भी देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए 2009 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को कुल मतों का 28.55 फीसद हिस्सा और उसके खाते में 12 करोड़ वोट गए, जबकि 2014 में इसका मत प्रतिशत गिरकर 19.30 फीसद पहुंच गया और इसे महज 10.7 करोड़ मतदाताओं का वोट मिला।

पिछले लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को हुए मतों का नुकसान अधिक मायने रखता है, क्योंकि मतदाता सूची में इस बार 10 करोड़ नए वोटर जुड़े थे। दूसरी तरफ 2009 में कुल 7.8 करोड़ वोट पाने वाली भाजपा का मत प्रतिशत दोगुने से भी अधिक रहा और उसे कुल 17 करोड़ वोट मिले। इसके चलते लोकसभा में कांग्रेस की शक्ति संख्या 206 सीटों से घटकर 44 सीटों तक सिमट गई। इस संदर्भ में 2014 के लोकसभा चुनावों के राज्यवार अध्ययन से पता चलता है कि चुनावी क्षति से गुजर रही कांग्रेस पार्टी का नुकसान लगाए जा रहे अनुमान से कहीं अधिक व्यापक और गहरा है। कुछ राज्यों में विशेषकर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के हाथों अपनी राजनीतिक जमीन खोने के बाद पार्टी की अपनी इच्छाशक्ति भी जाती रही। यदि चुनाव के तथ्यों पर नजर डालें तो साफ होता है कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी से जनता कितनी नाराज थी। कांग्रेस गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, ओड़िशा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, झारखंड, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गोवा में एक भी सीट नहीं जीत सकी। इसी तरह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और असम आदि राज्यों में कांग्रेस की सफलता एक अंक तक सिमट कर रह गई। कर्नाटक और केरल समेत कुछ राज्यों में बेहतर की आकांक्षा पाले कांग्रेस दो अंकों तक भी नहीं पहुंच सकी। यदि मत प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो कई राज्यों में पार्टी का प्रदर्शन सर्वाधिक खराब रहा। इनमें से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 7.5 फीसद, आंध्र प्रदेश में 11.5, पश्चिम बंगाल में 9.6, बिहार में 8.4, झारखंड में 13.3 और तमिलनाडु में महज 4.3 फीसद वोट मिले। हालांकि यह सही है कि किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में अंतिम तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह बिल्कुल साफ है कि देश के कई राज्यों में कांग्रेस की गिरावट के संकेत हैं।

पिछले लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को हुए मतों का नुकसान अधिक मायने रखता है, क्योंकि मतदाता सूची में इस बार 10 करोड़ नए वोटर जुड़े थे। दूसरी तरफ 2009 में कुल 7.8 करोड़ वोट पाने वाली भाजपा का मत प्रतिशत दोगुने से भी अधिक रहा और उसे कुल 17 करोड़ वोट मिले। इसके चलते लोकसभा में कांग्रेस की शक्ति संख्या 206 सीटों से घटकर 44 सीटों तक सिमट गई। इस संदर्भ में 2014 के लोकसभा चुनावों के राज्यवार अध्ययन से पता चलता है कि चुनावी क्षति से गुजर रही कांग्रेस पार्टी का नुकसान लगाए जा रहे अनुमान से कहीं अधिक व्यापक और गहरा है।

आजादी के दशकों बाद तक कांग्रेस उत्तर प्रदेश और बिहार में शासन करती रही, लेकिन अब यहां इसका किला पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। 1984 में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की कुल 85 में से 84 सीटों पर जीत मिली और उसे 51 फीसद वोट मिले थे, लेकिन इसके

बाद पार्टी को राज्य में लगातार गिरावट का दौर देखना पड़ा। हालांकि 2009 में किसी तरह से कांग्रेस ने सम्मानजक 21 सीटें जीतीं और उसे कुल 18.25 फीसद मत प्रतिशत मिले, लेकिन 2014 में कांग्रेस की बुरी हार हुई और उसे महज दो सीटों यानी रायबरेली में सोनिया गांधी और अमेठी में राहुल गांधी को जीत मिली। उसका मत प्रतिशत सिकुड़कर 7.5 फीसद पहुंच गया। 1980 के उत्तारार्ध में अपनी जमीन खोने के बाद कांग्रेस कभी भी उबर नहीं सकी। बिहार की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 1984 में कांग्रेस को यहां कुल 48 सीटों पर जीत मिली थी और 52 फीसद वोट मिले थे, लेकिन इस वर्ष यह मात्र 2 सीटें जीत सकी और मत प्रतिशत भी सिकुड़कर 8.4 रह गया।

वर्षों से कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी का रुतबा खोती जा रही है और उसे लालू यादव के राजद जैसे क्षेत्रीय दलों की जरूरत पड़ रही है। कई राज्यों विशेषकर पश्चिम बंगाल, ओड़िशा और अब आंध्र प्रदेश में इस पार्टी के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। पश्चिम बंगाल में 1977 में कम्युनिस्टों के हाथों हारने से पूर्व कांग्रेस ने यहां लंबे समय तक शासन किया था। इसके बाद यहां की सत्ता 34 वर्षों तक वामपंथियों के हाथ में रही, लेकिन कांग्रेस कभी भी अपनी जमीन वापस नहीं पा सकी। आठवें दशक की शुरुआत में कांग्रेस की एक युवा जुझारू महिला ममता बनर्जी उम्मीद बनकर उभरीं। उन्होंने मार्क्सवादियों का सामना किया। जैसे जैसे उनका राजनीतिक उभार हुआ पार्टी हाईकमान यानी नेहरू-गांधी परिवार एक मजबूत और स्वतंत्र नेता के तौर पर उन्हें सहन नहीं कर सका। कांग्रेस उनकी उग्र राजनीति की फसल तो काटना चाहती थी, लेकिन वह उन्हें दबाकर भी रखना चाहती थी। हाईकमान के इस षड्यंत्र से आजिज आकर ममता बनर्जी फूट पड़ीं और अलग तृणमूल कांग्रेस का गठन किया। इसके बाद राज्य में दूसरे स्थान पर काबिज कांग्रेस पार्टी को ममता ने तीसरे स्थान पर धकेल दिया। इस क्रम में मई 2014 पार्टी के लिए एक और बड़ा झटका साबित हुआ। इस राज्य में अब भाजपा एक मजबूत दावेदार के तौर पर उभरी है और मत प्रतिशत के लिहाज से कांग्रेस को चौथे स्थान पर ढकेल दिया है।

ओडिशा एक अन्य राज्य है जहां कांग्रेस को स्थानांतरित करके भाजपा अब मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाने को तैयार है। आंध्र और तेलंगाना के तौर पर विभाजन के बाद अब आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस की हालत कहीं अधिक खराब है। 2009 के लोकसभा चुनावों में सफाया करने वाली कांग्रेस इस बार बुरी तरह से हारी है। इसके ज्यादातर प्रत्याशियों को 3 से 4 फीसद मत मिले। इस राज्य में यह पार्टी अब तेलुगू देसम, वाइएसआर कांग्रेस और भाजपा के बाद चौथे स्थान पर है। यहां भी कांग्रेस के उभार की कोई संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में भी पार्टी कमजोर है। कर्नाटक को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में मत प्रतिशत के लिहाज से भाजपा और कांग्रेस के बीच अंतर बहुत अधिक है। इन सभी बातों के मद्देनजर कोई भी कह सकता है कि नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। हालांकि अभी कुछ काम किए जाने शेष हैं।

कांग्रेस के कई नेता जैसे दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि राहुल गांधी लोकसभा में पार्टी का नेतृत्व करें। ऐसे नेता वस्तुत: कांग्रेस मुक्त भारत के रूप में मोदी के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक बनने का ही काम कर रहे हैं। ■

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं।)

वर्षों से कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी का रुतबा खोती जा रही है और उसे लालू यादव के राजद जैसे क्षेत्रीय दलों की जरूरत पड़ रही है। कई राज्यों विशेषकर पश्चिम बंगाल, ओड़िशा और अब आंध्र प्रदेश में इस पार्टी के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। पश्चिम बंगाल में 1977 में कम्युनिस्टों के हाथों हारने से पूर्व कांग्रेस ने यहां लंबे समय तक शासन किया था। इसके बाद यहां की सत्ता 34 वर्षों तक वामपंथियों के हाथ में रही, लेकिन कांग्रेस कभी भी अपनी जमीन वापस नहीं पा सकी।

मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में भी पार्टी कमजोर है। कर्नाटक को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में मत प्रतिशत के लिहाज से भाजपा और कांग्रेस के बीच अंतर बहुत अधिक है। इन सभी बातों के मद्देनजर कोई भी कह सकता है कि नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है।

एक माह के कार्यकाल में अच्छे दिनों की बिसात

✍ जयकृष्ण गौड़

मीडिया में इस चर्चा को अधिक महत्व दिया जा रहा है कि भाजपा की नई सरकार केन्द्र में स्थापित हुए एक माह हो चुका है। यह किस ष्टि से पूर्व की यूपीए सरकार से बेहतर है ? कूटनीति, सुरक्षा तैयारी और आर्थिक दृष्टि से यह सरकार पूर्व सरकार से कितनी बेहतर है। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व पर देश की जनता ने विश्वास किया। भाजपा नेतृत्व भी जनता का विश्वास जीतने में इसलिए सफल रहा कि श्री मोदी ने गुजरात में जन इच्छा के अनुकूल विकास किया है। अब मोदी सरकार के एक माह के काम काज का आंकलन होना चाहिए, हो भी रहा है। उपलब्धियों का गणित सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आता। बीमार को कड़वी दवा दिये बिना वह रोग मुक्त नहीं हो सकता, यह तर्क लोगों को गले नहीं उतरता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी यह सवाल महत्व का है कि नई सरकार के कामकाज का प्रभाव आम लोगों पर क्या हुआ और सरकार की नीतिगत दिशा से आम आदमी को आभास कैसा हुआ है।

भविष्य के सपनों का विशेष सरोकार नहीं रहता। अभी तो महंगाई का ग्राफ बढ़ा है, बेरोजगारी यथावत है। रेल किराये में १४.२ की वृद्धि का मामला विपक्षी दलों का मुद्दा बन गया है। मुद्दाविहीन विपक्ष को इस वृद्धि से प्रहार का हथियार मिल गया है। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में विधानसभा के चुनाव है, इसलिए भाजपा विरोधी दल इस किराया वृद्धि का बाजा बजाकर लोगों को प्रभावित कर सकते है। लोगों को परिस्थिति का तर्क समझ में आना कठिन है, वे नई सरकार में ऐसा बदलाव देखना चाहते हैं जिससे उन्हें आभास हो कि यह सरकार कांग्रेसनीत सरकार से बेहतर है।

यदि मोदी सरकार के एक माह के कार्यकाल की समीक्षा इस आधार पर हो सकती है कि उसने केन्द्र में स्थापित होते ही सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने का निर्णय लिया। यह निर्णय गुजरात के विकास की चमक बढ़ा देगा। बिजली, सिंचाई और पेयजल की समस्या इस निर्णय से हल हो सकेगी। इस निर्णय के साथ ही गुजरात की आनंदबेन सरकार ने सरदार सरोवर बांध पर गेट बनाने का काम प्रारंभ कर दिया। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर का विरोध केवल मप्र के निमाड़ क्षेत्र तक सीमित है। गुजरात में इस विरोध का आंशिक प्रभाव भी नहीं है। अब तो मेधा पाटकर के एनजीओ को विदेशी मोटा चंदा मिलने के समाचार के साथ यह भी संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि विदेशी ताकतें भारत के विकास में अवरोध पैदा करने के लिए इस प्रकार के एनजीओ को मदद देती है।

सरकार ने इस प्रकार के एनजीओ को मिलने वाली मदद की जांच कराने का निर्णय लिया है। इस बारे में आम आदमी पार्टी के अचानक उभार के कारणों की समीक्षा हो सकती है, इस सच्चाई को सब जानते है कि भाजपा की बढ़त को रोकने और राजनैतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए एनजीओ ने आम आदमी पार्टी की भरपूर मदद की। करोड़ों का चंदा एकत्र हो गया। इस चंदे के बल पर इस पार्टी ने चुनाव लड़ा। चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी को देशी और विदेशी चंदा मिलता रहा। चुनाव के बाद शायद यह आभास हो गया कि आम आदमी पार्टी नरेन्द्र मोदी की आंधी रोकने में पूरी तरह असफल हुई है, इसलिए मिलने वाले चंदे के प्रवाह पर रोक लग गई और आप पार्टी जो कांग्रेस का विकल्प देने का दावा करती थी, उसकी जनता ने दुर्गति कर दी।

अलग प्रकार का राजनैतिक विकल्प का तर्क किसी को समझ नहीं आता। पानी के बुलबुले की तरह इस पार्टी का उभार हुआ और अब आप के लिए

अब मोदी सरकार के एक माह के काम काज का आंकलन होना चाहिए, हो भी रहा है। उपलब्धियों का गणित सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आता। बीमार को कड़वी दवा दिये बिना वह रोग मुक्त नहीं हो सकता, यह तर्क लोगों को गले नहीं उतरता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी यह सवाल महत्व का है कि नई सरकार के कामकाज का प्रभाव आम लोगों पर क्या हुआ और सरकार की नीतिगत दिशा से आम आदमी को आभास कैसा हुआ है।

अस्तित्व बचाने का सवाल है। वैसे तो कांग्रेस के पास भी विरोध का कोई मुद्दा नहीं बचा है। उसके केवल 44 प्रत्याशी जीते है, यह संख्या उत्तरप्रदेश में विजयी हुए भाजपा सदस्यों से भी कम है। अब तो कांग्रेस सदस्यों की संख्या इतनी भी नहीं है कि इसका नेता मान्यता प्राप्त विपक्षी दल का नेता बन सके। कांग्रेस उन मामलों को लेकर बयानबाजी कर रही है जिनका न कोई आधार है और न कोई प्रमाण है।

अभी तो रेल किराया वृद्धि का झुनझुना बजाकर वह विरोध दर्ज करा रही है। लेकिन भाजपा की मोदी सरकार को अपने कामों के द्वारा आम लोगों को यह आभास कराना होगा कि यह सरकार पूर्व की कांग्रेसनीत सरकारों से बेहतर है, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केन्द्र सरकार के चरित्र को बदलने की कोशिश की है। सभी मंत्रियों को सौ दिन में परिणाम देने के निर्देश दिये है। प्रशासन में भी कसावट आई है, कर्मचारी, अधिकारी बारह घंटे काम कर रहे है। श्री मोदी ने सचिव स्तर के अधिकारियों से कहा है कि उन्हें कोई कठिनाई हो तो वे सीधे पीएम आफिस से सम्पर्क कर सकते है।

सुरक्षा की दृष्टि से सार्थक पहल प्रारंभ हो गई सुरक्षा मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि सेना की आवश्यकताओं को पूरा किया जायेगा। विक्रमादित्य बेड़े को नौसेना में शामिल कर दिया गया है। स्वदेशी जहाज भी तैयार है। कूटनीतिक दृष्टि से शपथविधि समारोह में ही सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत के साथ आतंकवाद से संघर्ष करने का आश्वासन दिया है। जो अमेरिका श्री मोदी को वीजा देने में आना कानी करता था, वह भी उन्हें अमेरिका आने का निमंत्रण दे रहा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बांग्लादेश जाकर बांग्लादेश की ओर से हो रही घुसपैठ पर चर्चा की है। चीन की कंपनियों की ओर से निवेश करने की पहल प्रारंभ हुई है। इस प्रकार विकास के क्षेत्र में बंद दरवाजों को खोलने में मोदी सरकार सफल हुई है। शक्ति संपन्न और समृद्ध भारत के उद्देश्य को पूरा करने में मोदी सरकार जुट गई है। नदियों को शुद्धिकरण की दृष्टि से भी पहल प्रारंभ हो गई है।

जब हमने सरकार बनाई, तो कुछ लोगों का मानना था कि चीजे समझने में मुझे एक साल या अधिक लगेंगे। इस प्रकार मोदी सरकार ने काम करने वाली सरकार की छवि बनाई है। काले धन पर एसआईटी बनाना। काम बारिश की स्थिति से निपटने का रोड़ मेप तैयार करना, जमाखोरी को खत्म करने और खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने की पहल प्रारंभ हो गई है और क्या कर सकती है एक माह की सरकार।

गंगा यमुना के साथ अन्य नदियों को भी गंदगी से मुक्त करने का निर्णय सरकार ने लिया है। जो विपक्ष रेल किराया भाड़ा में वृद्धि और बढ़ती महंगाई के मामले में मोदी सरकार को घेर रहा है। उनसे यह सवाल पूछा जा सकता है कि पं. नेहरू से लेकर इंदिराजी, नरसिंहराव, राजीव गांधी और यूपीए गठबंधन की मनमोहन सरकार ने अपने एक माह के कार्यकाल में ऐसे कितने काम किये जिससे जनता को यह आभास हुआ कि सरकार उनके हित में बेहतर काम कर रही है। जुलाई से लोकसभा का पहला सत्र हो रहा है, आर्थिक दृष्टि से नीतिगत दिशा का पता चल जायेगा। अन्य सैद्धान्तिक मामलों को निपटाने में मोदी सरकार किस चतुराई से काम करेगी, यह भी देखना है। हालांकि चुनाव में कांग्रेस और अन्य कथित सेक्यूलर दलों ने नरेन्द्र मोदी की कट्टर छवि प्रस्तुत करने की कोशिश की थी लेकिन एक माह के कार्यकाल से यह जाहिर हो गई की श्री मोदी उदारवादी और संवेदनशील है, वे जनता की भावना और अपेक्षाओं को पूरा करने में जुट गये हैं। उनका यह कथन उनके व्यवहार में दिखाई दे रहा है कि हमें देश के लिए जीना है।

इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एक माह के कार्यकाल के संबंध में अपने ब्लॉग में कहा है कि हर नई सरकार को कुछ समय मिलता है, जिसे मीडिया के कुछ मित्र हनीमून पीरियड़ कहते है। पुरानी सरकारों ने तो हनीमून पीरियड सौ दिन और उससे भी अधिक बढ़ाया। सौ दिन तो छोडिये सौ घंटे के भीतर ही मुझ पर आरोप लगने लगे। ६७ वर्षो की तुलना एक महीने में नहीं की जा सकती, मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरी टीम ने हर पल लोगों के कल्याण की सोची। हमारा हर फैसला राष्ट्रहित को समर्पित था। जब हमने सरकार बनाई, तो कुछ लोगों का मानना था कि चीजें समझने में मुझे एक साल या अधिक लगेंगे। इस प्रकार मोदी सरकार ने काम करने वाली सरकार की छवि बनाई है। काले धन पर एसआईटी बनाना। काम बारिश की स्थिति से निपटने का रोड़मैप तैयार करना, जमाखोरी को खत्म करने और खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने की पहल प्रारंभ हो गई है और क्या कर सकती है एक माह की सरकार।■

नवनिर्वाचित सांसदों के लिए दो दिवसीय भाजपा प्रशिक्षण शिविर

''सदन में अनुशासित आचरण और जिम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण''

हाल ही में सत्तारूढ़ भाजपा और लोकसभा सचिवालय ने संसद में पहली बार आने वाले सांसदों का एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। यह प्रयास लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मील का पत्थर होगा जिससे न केवल प्रभावी लोकतांत्रिक नेतृत्व तैयार हो जाएगा, अपितु सुशासन के मॉडल तैयार करने में प्रशिक्षण की संस्कृति को भी तयार करेगा। यदि प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षार्थी इन कार्यक्रमों को भलीभांति सीख लें तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वर्षो में बेहतर वैधानिक कार्यवाही का आरम्भ हो पाएगा।

प्रशिक्षण शिविर में नवनिर्वाचित सांसदों को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पार्टी सांसदों से अनुरोध किया वे जिम्मेदार और सकारात्मक रूख अपनाएं। उन्होंने कहा कि लोगों में बड़ी भारी उम्मीदें हैं और हमें उनकी उम्मीदों के स्तर तक पहुंचना ही होगा। श्री मोदी भाजपा द्वारा सूरजकुण्ड में आयोजित प्रशिक्षण सत्र का उद्घाटन कर रहे थे जिसमें संसद के दोनों सदनों के पहली बार बने 180 सांसद शामिल हुए। ऐसे कई पुराने पार्टी के कार्यकर्ता थे जो पहली बार संसद में निर्वाचित हुए थे। ऐसे भी कई लोग थे जो भाजपा में पहली बार शामिल हुए थे, जिन की कांग्रेस की पृष्ठभूमि थी और जो भाजपा संस्कृति सीखने के लिए इच्छुक थे। इनमें कई पोस्ट-ग्रेजुएट, प्रबंध-विशेषज्ञ, गायक और कलाकार, किसान एवं प्रोफेशनल्स थे। सर्वप्रथम इन लोगों ने प्रशिक्षण बैठक में विचारों का आदान-प्रदान किया।

अपने अध्यक्षीय भाषण में पार्टी अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने पार्टी के प्रशिक्षण प्रकोष्ठ एवं संसदीय कक्ष के प्रयासों की सराहना की और यह विश्वास व्यक्त किया कि इस प्रकार के प्रयासों से ही हमारी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था सर्वोत्कृष्ट लोकतंत्र

का रूप ले सकती है। सांसदों को अपने निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रति जिम्मेदारी का स्मरण कराते हुए उन्होंने कहा कि हमें सदन में व्यवस्थित और अनुशासित आचरण में रहना होगा। उनका कहना था कि नए सदस्यों को पुस्तकालय में जाना चाहिए, पुस्तकों का भलीभांति पढ़ना चाहिए और विषयों पर पूर्ण ज्ञान रखना चाहिए। जब कभी भी कोई सदस्य बोलता है तो उससे किसी को घबराहट महसूस नहीं होनी चाहिए। कृपया संसद के नियमों और कार्यवाहियों को पढ़ें। यह तो उनके लिए भगवद्गीता के समान होगा।

वरिष्ठ पार्टी नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और भारतीय राजनीति के प्रति हमारी ऐसी दीर्घकालीन दूरदृष्टि होनी चाहिए जिसमें सार्वजनिक जीवन में बहुसंख्यकों तथा अल्पसंख्यकों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं चाहिए। वास्तव में तो हमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक श्रेणियों को एकदम अप्रासंगिक बना देना चाहिए और साथ ही लोगों ने अधिकार और सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए ताकि लोग अपने-अपने मजहबों के अनुसार चल सकें।

उन्होंने कहा कि गवर्नेंस की परम्परानुसार विकास चुनौतियों के समाधान में सरकारी तंत्र और लोगों के बीच कोई सम्बन्ध नहीं होता है। यही कारण है कि हमें वांछित परिणाम नहीं मिल पाते हैं चाहे हम इन विभिन्न मुद्दों पर कितना ही खर्च क्यों न कर डालें। जब नरेन्द्र भाई कहते हैं, वह बात सही है कि विकास को हमें लोगों का अभियान बना देना है। इसे करने के लिए कई बातें करने की आवश्यकता

है। किंतु आज के प्रसंग में जो बात प्रासंगिक है, वह यह है कि हमारे मंत्रियों और सांसदों को सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए लोगों को शामिल कर उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। मेरा सुझाव है कि नए पार्टी अध्यक्ष और कुछेक मंत्रियों के समूह और पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री के मार्गनिर्देशन में इस अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभदायक विचार को कार्यान्वित करने के तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह भाजपा के लिए लाभप्रद होगी क्योंकि जब हमारे मंत्रीगण और सांसद लोगों के अभियान को विकास बनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो स्वयं लोग निश्चित तौर पर भावी चुनावों में हमारा साथ देंगे।

नि:संदेह, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का भाषण, अत्यंत प्रभावशाली रहा जिन्होंने प्रथम बार बने सांसदों से आग्रह किया कि वे अपना कर्त्तव्य समझकर मिशन की भावना से स्वयं को तैयार करें तथा कम से कम एक ऐसा विषय चुने जिसमें वह स्वयं अध्ययन करते हुए अपने को पारंगत बना लें। सांसद एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है और उसे गंभीरता से देखा जाना चाहिए। याद रखिए, लोग आपकी परफोर्मेंस को न केवल सदन में देख रहे होंगे हैं, बल्कि बाहर के लोग भी देखते हैं। विपक्ष की तरफ से हमारा सत्ता की तरफ बढ़ना केवल दूसरी 'साइड' तक बढ़ने तक सीमित नहीं है। यह महत्वपूर्ण परिवर्तन है और हमें इस अर्थ को सार्थक बनाना चाहिए। सांसदों से अनुरोध करते हुए उन्होंनें कहा कि आप लोग छोटे-मोटे मुद्दों से भ्रमित न हो और कहा कि राजनीति में कहीं भी विराम की स्थिति नहीं आती है।

पार्टी सांसदों से अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा कि वे किसी भी नकारात्मकता की स्थिति में न जाए और इस बात पर जोर दिया कि संसदीय पार्टी के प्रति हमारी दृष्टि पारस्परिकता और सहयोगी भावना रहनी चाहिए। हम सब एक परिवार है और सभी एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। बेहतर होगा, नए मित्र बनाएं, एक-दूसरे से सीखें और एक प्रकार की सामूहिकता का भाव पैदा करें। उन्होंने पार्टी सांसदों को स्मरण कराते हुए कहा कि यह प्रशिक्षण को रीति-रिवाज जैसा समझ कर न चलें, बल्कि भाजपा की क्षमता निर्माण की एक लम्बी और गहरी परम्परा है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें एक जुट वाला संगठन बनना चाहिए। हम कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो एक छत के नीचे इकट्ठे होने वाले व्यक्ति मात्र है। यह प्रशिक्षण शिविर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने को बनाया गया है ताकि हम आम आदमी की महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकें। यह प्रशिक्षण हमारा वह लक्ष्य है जिससे हम लोगों के प्रतिनिधि बन सकें। हमें लोगों की आकांक्षाएं पूरी कर लोगो ंका विश्वास जीतना है। हमारी सामूहिक शक्ति, हमारा आचरण और हमारा कठोर परिश्रम ही सदन में गहरा प्रभाव डाल पाएगा। यदि हम एक बिल पारित कर भारत के गरीब लोगों की समस्या सुझा पाएंगे तो आगे की पीढ़िया हमारी सरकार को याद रखेंगी। हमें सकारात्मक पहलू पर अधिक बोलना चाहिए। हमारा रवैय्या नकारात्मक न हो।

प्रशिक्षण शिविर में वातावरण अनौपचारिक रूप से अत्यंत मित्रतापूर्ण था। विशेष बात यह देखने में आई कि प्रो. जीतेन्द्र सिंह जैसे मंत्री भी अन्य साथी सांसदों के साथ विद्यार्थी की तरह हीश्रोताओं के बीच बैठे रहे। कोई भी व्यक्ति स्टेट्स जागरूकता से पीड़ित नहीं था और न ही किसी प्रकार का शिष्टाचार का बोझ पड़ा था। बहुतों को तो इस बात से आराम मिला कि अधिकांश नए सांसद अपने को एक नए विद्यार्थी की तरह बैठे हुए थे।

कभी कभी उनमें विश्वास की कमी भी नजर आती थीं तो कभी कभी वे भ्रमित लगते थे। परन्तु यह स्वाभाविक है क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ सीखना चाहते हैं। यथासंभव अधिक से अधिक समय सदन में बिताएं, पूरा ध्यान दें, बड़े लोगों से सीखने की प्रवृत्ति बनाएं और आप में विश्वास पैदा हो जाएगा।

केन्द्रीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज और केन्द्रीय वित्त एवं रक्षामंत्री श्री अरुण जेटली ने उन्हें बहुमूल्य टिप्स दिए किस प्रकार संसद में कार्य करें। दोनों ने ही नए सांसदों से कहा कि इन्हें अधिक से अधिक समय संसदीय लाइब्रेरी में बिताना चाहिए।

एक दूसरे सत्र में केन्द्रीय संसदीय

अपना कर्त्तव्य समझकर मिशन की भावना से स्वयं को तैयार करें तथा कम से कम एक ऐसा विषय चुने जिसमें वह स्वयं अध्ययन करते हुए अपने को पारंगत बना लें। सांसद एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है और उसे गंभीरता से देखा जाना चाहिए। याद रखिए, लोग आपकी परफॉर्मेंस को न केवल सदन में देख रहे होंगे हैं, बल्कि बाहर के लोग भी देखते हैं। विपक्ष की तरफ से हमारा सत्ता की तरफ बढ़ना केवल दूसरी 'साइड' तक बढ़ने तक सीमित नहीं है। यह महत्वपूर्ण परिवर्तन है और हमें इस अर्थ को सार्थक बनाना चाहिए।

कार्यमंत्री श्री वेंकैया नायडू ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों और संगठन के बीच समन्वय बनाया जाना चाहिए। इन बातों से बहुत से प्रथम बने सांसदों की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही। एक सांसद का कहना था कि सचमुच हमें संसद के बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते थे। एक युवा महिला सांसद का कहना था कि मैं इससे पूर्व जिला जनप्रतिनिधि थी और विशाल संसद भवन को देखकर मुझे संकोच महसूस हुआ, बल्कि एक तरह से कुछ घबरा गई। अब मुझे संसद में भाग लेने के लिए प्रभावशाली ढंग की जानकारी मिली है, मैं बहुत राहत महसूस करती है और मुझ में भारी विश्वास पैदा हुआ है।

दिल्ली के विधान सभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर एडवोकेट आलोक कुमार ने भाजपा के इतिहास को विस्तार से बताते हुए भारतीय राजनीति में उसके योगदान का उल्लेख किया। बहुत से युवा सांसदों ने 1951 से लेकर भाजपा की यात्रा की गाथा सुनी, जब उस समय जनसंघ की स्थापना हुई थी। संक्षेप में ही सही, आलोक जी ने पार्टी के संगठनात्मक रूपरेखा को भी चित्रांकित किया।

श्री लालकृष्ण आडवाणी का समापन भाषण तो एक मार्गदर्शक के रूप में आशीर्वाद की तरह था जिसमें उन्होंने सांसदों को याद कराया कि उन पर लोगों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की भारी चुनौती सामने खड़ी है।

पार्टी संगठन महामंत्री श्री रामलाल द्वारा आयोजित एक सत्र में बैठक में आए सांसदों ने कुछ प्रबंध-खेलों का आनन्द उठाया। सूरजकुण्ड से शिविर समाप्ति पर बाहर निकलते हुए सभी ने महसूस किया कि उन्हें नए मित्र मिले, नए परिचित मिले और यह भी महसूस किया कि वे ही मात्र 'फ्रेशर्स' नहीं हैं।■

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर कार्यक्रम आयोजित

भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयन्ती के अवसर पर भाजपा दिल्ली प्रदेश की ओर से 6 जुलाई को पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया गया। भाजपा की सभी जिला इकाईयों ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति संगोष्ठियों का आयोजन किया।

इस अवसर पर भाजपा प्रदेश प्रभारी एवं सांसद श्री प्रभात झा ने कहा कि डॉ. मुखर्जी का जीवन चरित्र न सिर्फ आज बल्कि आने वाले युगों युगों तक हर राष्ट्रवादी एवं भाजपा कार्यकर्ता को प्रेरणा देता रहेगा। श्री झा ने उपस्थित कार्यकर्ताओं से कहा कि डॉ. मुखर्जी ने जहां देश की एकता के लिये कार्य किया, वहीं देश की शिक्षा व्यवस्था पर भी उनका चिंतन मौलिक था। भारत के पहले उद्योग मंत्री के तौर पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत की उद्योग नीति को भी रचा।

केन्द्रीय मंत्री एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. हर्ष वर्धन ने डॉ. मुखर्जी को याद करते हुये आज कहा कि डॉ. मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन में नारा दिया था – एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान- नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे। उन्होंने इस नारे को अपना बलिदान देकर सार्थक किया। उन्होंने कहा कि निश्चय ही आज भाजपा की सरकार देख डॉ. मुखर्जी मुस्कुरा रहे होंगे पर उनके सपनों का भारत तब ही साकार होगा जब कश्मीर पूर्णतः भारत का संतुष्ट राज्य होगा।

पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं सांसद श्री विजय गोयल, सांसद श्री रमेश बिधूड़ी,

श्री महेश गिरी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री मांगेराम गर्ग, संगठन महामंत्री श्री विजय शर्मा, विधायक श्री जगदीष मुखी, महामंत्री श्री जय प्रकाश, श्रीमती शिखा राय, महापौर श्री योगेन्द्र चांदोलिया, श्रीमती मीनाक्षी, सदन के नेता श्री सुभाष आर्य सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने फिरोजशाह कोटला पार्क में डॉ. मुखर्जी के मूर्ति स्थल पर आयोजित समारोह में पुष्पांजली अर्पित की।

इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली प्रदेश के सभी 14 जिलों में आज नई पीढ़ी को डॉक्टर मुखर्जी के जीवन चरित्र से अवगत कराने के लिये संगोष्ठियों का आयोजन किया गया, जिनमें श्री रमेश बिधूड़ी, श्री प्रवेश वर्मा, श्री मनोज तिवारी, श्रीमती मीनाक्षी लेखी, सुश्री आरती मेहरा, श्री मांगेराम गर्ग, श्री विजेन्द्र गुप्ता, प्रो. जगदीश मुखी, श्री पृथ्वीराज साहनी, श्री आशीष सूद, डॉ. सम्बित पात्रा, श्री महेश चन्द्र शर्मा एवं श्री मेवाराम आर्य सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को जिलावार संबोधित किया। ■

'डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मानवाधिकार' विषयक संगोष्ठी आयोजित

✍ संवाददाता द्वारा

गत 2 जुलाई 2014 को भाजपा मानवाधिकार प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय कार्यसमिति में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मानवाधिकार विषय पर संगोष्ठी में गृहराज्यमंत्री श्री किरण रीजिजू ने कहा मानवाधिकारों की रक्षा भाजपा एकात्म मानववाद के अनुसार करती है। हमारी पार्टी प्रत्येक व्यक्ति की चिंता करती है। किसी के भी अधिकारों का हनन नहीं होगा।

राष्ट्रीय महामंत्री संगठन श्री रामलाल ने प्रकोष्ठ के सभी प्रदेश संयोजक से एवं देश के सभी मानवाधिकार प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं से समाज के सभी वर्गों से जुड़कर मानवाधिकार हनन किसी का भी न हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिले तथा पार्टी के कार्यकर्ता उसके साथ खड़े रहें एवं पार्टी तथा सरकार तक पीड़ित की आवाज पहुंचे जिससे न्याय करने में देरी न हो।

केन्द्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने कहा मानवाधिकारों का हनन देश में किसी का नहीं होगा। हम ऐसे मैकेनिज्म का इन्तजाम कर रहे हैं जिससे आप तक जल्दी ही सब सूचनाएं आपके घर तक पहुंचनी शुरू हो जायेंगी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी ने कहा देश के प्रत्येक नागरिक से जुड़ने के लिए पार्टी का महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ है। मानवाधिकार के कार्यकर्ताओं को अधिक मेहनत करनी चाहिए।

मुख्य अतिथि श्री इन्द्रेश कुमार ने कहा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान मानवाधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है। आपने मानवाधिकार और डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी विषय को जोड़कर मानवाधिकार की सही परिभाषा दी है। डॉ. मुखर्जी जीवन भर

मानावधिकारों की रक्षा करते रहे तथा मानवाधिकार रक्षा में ही उन्हें जेल हुई तथा उनके प्राण गये।

उन्होंने कहा कि कश्मीर की महिलाओं के बाहर शादी करने पर उनके अधिकार समाप्त हो जाते हैं पर परिवार के बाहर शादी करने पर ऐसा नहीं होता है। यह महिलाओं के अधिकारों का हनन है। जो नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर अधिकार तय न हो मानवता के आधार पर अधिकार तय हो तथा कर्तव्य एवं अधिकार का संतुलन बना रहे। रूपये और डालर के अन्तर का असंतुलन भी उन्होंने विस्तार से बताया।

राष्ट्रीय मंत्री श्री श्याम जाजू ने मानवाधिकार प्रकोष्ठ के संयोजकों को सम्मानित किया तथा पार्टी के कार्यकर्ताओं को हर एट्रोसिटी में पहले पहुंच कर मदद करने को कहा, बैठक में राष्ट्रीय संयोजक सुधीर अग्रवाल ने भी विचार व्यक्त किये इस मौके पर उनकी लिखी हुई पुस्तक हयूमन राइट्स प्रेसपेक्टिव का नेताओं ने विमोचन किया।

बैठक में राष्ट्रीय सह संयोजक डॉ. शैलेन्द्र ठाकुर तथा कैलाश नाथ पिल्लै जी ने भी विचार रखे तथा वन्दे मातरम् गायन श्रीमती प्रतिभा जाजू ने किया, धन्यवाद राकेश खन्ना ने किया। इस मौके पर दिनेश जिन्दल, बृजेश भूटानी, शोभा उपाध्याय, अर्चना सिंहल एवं सभी प्रदेश संयोजक सह संयोजक एवं सभी राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता उपस्थित रहे।■

प्रादेशिक समाचार

मध्य प्रदेश

भाईचारा और विकास भाजपा का एकमात्र लक्ष्य : शिवराज सिंह चौहान

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने 25 जून को भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीतियां रही हैं कि सभी को न्याय सुनिश्चित हो। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकारों ने हमेशा दिलों को जोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हम भारत मां की इस माटी में जन्मे हैं, हम सभी एक परिवार के सदस्य है। भाजपा 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना में विश्वास रखती है, हमारे लिए सारी दुनिया एक परिवार की तरह है।

मध्यप्रदेश की धरती पर भी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता को एक परिवार की तरह माना है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से इंसानियत में दूरियां बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस ने अल्पसंख्यक भाईयों को इंसान न मानते हुए मात्र वोट बैंक माना। जनता से जो लोग भेद करने की बात करते है वो न्याय नहीं करते, वह सिर्फ वोट बैंक की तरफ देखते है। अल्पसंख्यक वर्ग वोट नहीं, वोट के बैंक भी नहीं है, वह इंसान है। और कोई भी राजनैतिक दल हमें इंसान मानकर व्यवहार करें न कि वोट बैंक मानकर। श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वर्षो से कांग्रेस ने गलत माहौल बना दिया है।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश में चल रही योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग शामिल न हों। हमने धर्म के आधार पर भेद नहीं किया है। धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास की राजनीति की है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इंसानियत को सामने रखकर सरकार चलाई है। अगर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है तो मुख्यमंत्री निकाह योजना भी चलाई है। लाड़ली लक्ष्मी का लाभ मुस्लिम बेटियों को भी बराबर मिला है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जमाने में 10 हजार से अधिक अल्पसंख्यक बेटा-बेटियों को स्कॉलरशिप नहीं मिली, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले एक साल में मध्यप्रदेश के 1 लाख 65 हजार अल्पसंख्यक बेटा-बेटियों को स्कॉलरशिप देने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 'स्कूल चलें हम' अभियान प्रारंभ किया है।

उन्होनें मोर्चा से आग्रह किया कि इस अभियान से जुड़कर मोर्चा ऐसे अल्पसंख्यक बेटा-बेटियों को, जो स्कूल नहीं जा पाते, उन्हें तालीम दिलाने में और प्रतिभा संवारने में मदद करें। मुख्यमंत्री ने मोर्चा से सामाजिक परिवर्तन के लिए चलाये जा रहे बेटी बचाओ अभियान से जुड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि जहां-जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें है वहां विकास, सुशासन और भाईचारा है।

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सरकारों ने कांग्रेस सरकारों से 10 गुना बेहतर काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकारें नहीं दिलों को जोड़ने का काम किया है, इस बात पर हमें गर्व करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार का एकमात्र लक्ष्य अमन-चैन, भाईचारा और विकास है।

पूर्व में मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल राशिद अंसारी एवं प्रदेश अध्यक्ष हिदायतुल्लाह शेख ने पार्टी के मोर्चा एवं प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय समन्वयक महेन्द्र पांडे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी जे.के.जैन, मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष तनवीर अहमद, पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री अरविन्द मेनन, मोर्चा के प्रदेश प्रभारी एवं पार्टी प्रवक्ता विजेन्द्रसिंह सिसोदिया, वरिष्ठ मंत्री अंतरसिंह आर्य एवं वरिष्ठ नेता आरिफ बेग का पुष्पहारों से स्वागत किया।

छत्तीसगढ़

उच्च शिक्षा के लिए अब मिलेगा सिर्फ एक प्रतिशत ब्याज पर ऋण

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को 8 जुलाई को एक नई खुशखबरी दी । उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीयकृत और निजी क्षेत्र के बैंकों से अब सिर्फ एक प्रतिशत ब्याज पर अधिकतम चार लाख रूपए का ऋण मिलेगा। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के घोषणा पत्र 2013 में किए गए वायदे के अनुरूप अधिकारियों को इस पर तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि डॉ. रमन सिंह ने राज्योत्सव 2012 के अवसर पर प्रदेश की युवाओं के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋणब्याज अनुदान योजना की घोषणा की थी। इस योजना में दो लाख रूपए से कम वार्षिक आमदनी वाले परिवारों के युवाओं को बैंकों से सिर्फ चार प्रतिशत की दर से अधिकतम चार लाख रूपए का ऋण प्राप्त करने की सुविधा मिल रही थी। डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अब इस योजना में ब्याज दर को घटाकर एक प्रतिशत कर दिया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार के वर्ष 2013 के घोषणा पत्र में युवाओं से यह वायदा किया गया था।

तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय ने आज यहां बताया कि घोषणा पत्र के इस वायदे पर अमल करते हुए तकनीकी शिक्षा संचालनालय ने प्रदेश के सभी इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एम.सी.ए. और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों वाले कॉलेज प्राचार्यों और संचालकों को इसके लिए परिपत्र जारी कर दिया है। इंजीनियरिंग शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कृषि इंजीनियरिंग आदि कई पाठ्यक्रम इसमें अधिसूचित किए गए हैं। परिपत्र में कहा गया है कि योजना का लाभ देने के लिए कॉलेज या संस्था परिसर में बैंकों से समन्वय कर ऋण शिविर लगाया जाए। इसके अलावा पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस योजना के क्रियान्वयन के लिए बैंकों से समन्वय किया जाए। कॉलेज परिसरों में लगने वाले इन शिविरों में संबंधित कॉलेजों में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से उनकी पात्रता के अनुसार निर्धारित प्रारूप में आवेदन लेकर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। श्री पाण्डेय ने बताया कि तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेशित ऐसे विद्यार्थियों को, जिनके परिवारों की वार्षिक आमदनी दो लाख रूपए से कम है, उन्हें मोरेटोरियम अवधि के बाद ऋण किश्तों के नियमित भुगतान की स्थिति में केवल एक प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा। शेष ब्याज की राशि का भुगतान राज्य सरकार की ओर से सीधे संबंधित बैंकों को किया जाएगा।

उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री पाण्डेय ने यह भी बताया कि प्रदेश के सोलह नक्सल प्रभावित आदिवासी बहुल जिलों के विद्यार्थियों को इस योजना में ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। इनमें बस्तर, बीजापुर, दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा), उत्तर बस्तर (कांकेर), नारायणपुर, सुकमा, कोण्डागांव, गरियाबंद, बलरामपुर-रामानुजगंज, सरगुजा, जशपुर, कोरिया, राजनांदगांव, बालोद, धमतरी और महासमुन्द जिले शामिल हैं। योजना के क्रियान्वयन के लिए बैंकों से समन्वय की दृष्टि से केनरा बैंक को नोडल बैंक और तकनीकी शिक्षा विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है।

श्री पाण्डेय ने बताया कि इच्छुक विद्यार्थियों को किसी भी सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र के बैंक से शिक्षा ऋण प्राप्त करने पर इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए तकनीकी शिक्षा संचालनालय ने पाठ्यक्रमों की सूची भी जारी कर दी है। इसमें बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (बी.ई.) मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग (एम.ई.) मास्टर टेक्नॉलॉजी (एम.टेक), बी-फार्मा, एम-फार्मा, डी-फार्मा, बी.एड., डी.एड., एम.सी.ए., बीपीएड, एमबीबीएस, बैचलर ऑफ होमियोपैथी मेडिसिन एण्ड सर्जरी (बीएचएमएस), बी.ए.एम.एस., बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बीडीएस), मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (एमडीएस), बैचलर ऑफ नेचरोपैथी एण्ड योग (बीएनवाईएस), बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एण्ड सर्जरी (बीयूएमएस), बैचलर ऑफ वेटेनरी साइंस (बी.व्ही.एस-सी), बैचलर ऑफ फिशरी साइंस, डेयरी टेक्नालॉजी, बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर, बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर (बी.आर्क.) आदि पाठ्यक्रम शामिल हैं।

राजस्थान

महंगाई पर नियंत्रण के हर संभव प्रयास होंगे : वसुंधरा राजे

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा है कि राज्य सरकार हर संभव प्रयास करेगी कि प्रदेश में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता में कोई कमी नहीं आए और आम आदमी को महंगाई से राहत मिले।

श्रीमती राजे 7 जुलाई को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान प्रदेश में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों के संबंध में उच्च स्तरीय समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मूल्य नियंत्रण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत दिलाने के लिए अधिकारियों का एक समूह गठित कर कंटीजेंसी प्लान तैयार करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उचित मूल्य की दुकानों में उपभोक्ताओं को पीडीएस वस्तुओं के साथ ही सस्ती दरों पर अच्छी क्वालिटी की आवश्यक खाद्य सामग्री जैसे आलू, प्याज, दाल, इत्यादि भी उपलब्ध हों, इसके लिए कार्ययोजना तैयार की जाए।

आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में नियंत्रण के लिए गठित यह समूह एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगा। अति. मुख्य सचिव कृषि, श्री अशोक संपतराम की अध्यक्षता में गठित यह चार सदस्यीय समूह प्रदेश में आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव, उनके उत्पादन एवं उपभोग की स्थिति का अध्ययन कर उन पर नियंत्रण, उपलब्धता तथा बाजार में आवक-जावक पर अपने सुझाव देगा। एसीएस सहकारिता, श्री राजहंस उपाध्याय, राजस्थान राज्य भंडारण निगम के सीएमडी श्री ललित मेहरा तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री सुबोध अग्रवाल इस समूह के सदस्य होंगे।

यह समूह प्रदेश में आलू एवं प्याज की स्टॉक सीमा निर्धारित करने के संबंध में भी अध्ययन कर सुझाव देगा। उल्लेखनीय है कि 3 जुलाई को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 के तहत केन्द्र सरकार ने राज्यों को आलू एवं प्याज की स्टॉक सीमा तय करने की छूट दी है।

बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात राज्यमंत्री श्री हेमसिंह भडाना, मुख्य सचिव श्री राजीव महर्षि, एसीएस कृषि श्री अशोक संपतराम, एसीएस सहकारिता श्री राजहंस उपाध्याय, प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री सुभाष गर्ग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलात विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री सुबोध अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

गुजरात

राज्य में पुलिस बल में महिलाओं के लिए होगा 33 फीसदी आरक्षण

गुजरात की मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने 24 जून को एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य के पुलिस बल में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।

गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री पटेल ने संवाददाताओं को बताया कि समाज में उत्थान के लिए महिलाओं को सशक्त करना जरूरी है। मेरी सरकार ने पुलिस बल में होने वाली नई भर्तियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। इसे सभी कैडरों में लागू किया जाएगा।

गुजरात सरकार ने ऐसे समय में यह फैसला किया है जब कई राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध में इजाफा हुआ है और उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दो नाबालिग लड़कियों के कथित बलात्कार और हत्या के बाद ऐसे मामले मीडिया की सुखिर्यों में हैं। श्रीमती पटेल ने गुजरात पुलिस अकादमी में पासिंग आउट परेड में शिरकत करने के बाद मीडिया से बातचीत में यह ऐलान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं ने पुलिस बल में हर स्तर पर अपनी सेवाएं दी हैं। जब एक मां ने खुद को समाज, राज्य और देश की सेवा के लिए तैयार किया है तो हमें उन्हें विशेष प्रशिक्षण एवं विशेष स्थान देना होगा। गुजरात के पुलिस महानिदेशक श्री पीसी ठाकुर ने कहा कि पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात होगा। ठाकुर ने कहा कि महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण तो नहीं है पर वहां पुलिस बल की कुल क्षमता में 10 फीसदी हिस्सेदारी महिलाओं की होती है जो देश में सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि गुजरात पुलिस में अभी महिलाओं की हिस्सेदारी चार से पांच फीसदी है। गुजरात पुलिस में स्वीकृत पदों की संख्या करीब 60,000 है।■